खबर छुपेगी नहीं छपेगी

दुर्गम ख़बर

राष्ट्रीय राजधानी से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष : 17 अंक 09 | दिल्ली, बुद्धवार 24 जुलाई 2024 | RNI-No. DELHIN/2008/2623 | पेजः 8 मूल्य : 1 रुपया

गरीबों,किसानों और महिलाओं के लिए खुला खजाना

मोदी सरकार का 'मंगलमय' बजट

- 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, एजुकेशन लोन 10 लाख रुपए कर दिया
- भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर जोर
- नौकरी और कौशल विकास पर 2 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करने का ऐलान
- महिलाओं-लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं पर 3 लाख करोड़ होंगे खर्च

नई दिल्ली (एजेंसी)। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कमर कस ली है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण पढ़ा तो यही बात नजर आई। निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट पेश किया है। यह मोदी सरकार का यह 13वां बजट है, जिसमें निर्मला ने कहा कि यह बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अपना विश्वास तीसरी बार जताया है। वहीं, मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से चल रही है। निर्मला के इस बजट में आम आदमी को थोड़ी सी राहत देते हुए नए टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत 3 लाख तक की इनकम अब टैक्स फ्री होगी। वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स से छूट पहले की ही तरह जारी रहेगी। यानी सरकार धीरे-धीरे नई टैक्स रिजीम की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने बजट में युवा, किसान, महिला और गरीब सबको फोकस किया है।

नीतिश को 59 हजार करोड़, नायडू को 15 हजार करोड़ की सौगात

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतिश कुमार के बिहार और

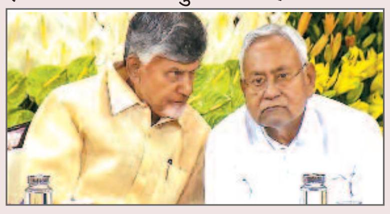

चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतिश कुमार की जेडीयू और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे चल रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ और आंध्र की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ दिए हैं।

यह बजट देश को समृद्धि देने वाला मिडिल क्लास को नई शक्ति देगा

- पीएम मोदी ने रखी अपनी बात, विपक्ष बोला-ये नीतिश और चंद्रबाबू से डरा हुआ

नई दिल्ली (एजेंसी)। मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश किया। ये उनका लगातार सातवां बजट था। बजट के साथ ही देश भर में इसे लेकर रिएक्शन भी आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बजट को गृहमंत्री शाह ने मोदी सरकार में आशावाद की नई भावना कहा है, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री देने वाले राज्य यूपी को कुछ नहीं मिला है। उधर, विपक्ष और इंडिया ब्लॉक से जुड़े नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना का नाम दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह नीतिश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है।

मोबाइल फोन सस्ते होंगे

सोना-चांदी पर भी ड्यूटी घटाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। अब बजट में गिनी-चुनी चीजें ही सस्ती या महंगी होती हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में जीएसटी लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। तो इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। बीते एक साल में सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगे हुए हैं।

युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 5 हजार महीना मिलेगा

मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। पीएम मोदी का यह युवाओं के लिए स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज है। इसके तहत युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने की मौका मिलेगा। साथ ही हर महीने 5 हजार रुपये का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा।

एजुकेशन लोन 10 लाख तक, ब्याज पर भी छूट

वित्त मंत्री ने घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए लोन 10 लाख तक किए जाने भी ऐलान किया। घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3 फीसदी की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

बनेंगे तीन नए एक्सप्रेस-वे

युवाओं के लिए 5 नई स्कीम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार में 3 एक्सप्रेसवे, भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्लांट के साथ ही पूर्वी राज्यों के डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय स्कीम का ऐलान किया है। वहीं जॉब-स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 नई योजनाओं की घोषणा की।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेस वे और बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनाया जाएगा। बिहार में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 26 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान है। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से 2400 मेगावॉट की क्षमता का पावर प्लांट बनेगा।

क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा

ये होंगी सस्ती	इनके बढ़ेंगे दाम
चमड़े के जूते	सिगरेट
कपड़े	हवाई जहाज से यात्रा
सोना-चांदी	प्लास्टिक का सामान
मोबाइल फोन	पेट्रोकेमिकल
मोबाइल चार्जर	इलेक्ट्रिक व्हीकल
कैंसर दवा	प्लेटिनम
बिजली के तार	एक्सरे मशीन
सोलर सेट्स	

संक्षिप्त समाचार

सुनीता विलियम्स के साथ स्पेस स्टेशन में मौजूद है सुपरबग

वॉशिंगटन (एजेंसी)। ये किसी साइंस-फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन उतना ही सच है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जिस अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (नासा) में पिछले डेढ़ महीने से ज्यादा समय से फंसी हुई हैं, वहां एक एक बहुत खतरा मौजूद है। ये खतरा एक सुपरबग है, जिसके बारे में कुछ समय पहले ही वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। आईआईटी मद्रास और नासा की जेट प्रपल्शन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में एक ऐसे बैक्टीरिया स्ट्रेन का पता लगाया है, जो कई बार म्यूटेशन करके बहुत शक्तिशाली बन चुका है। इसके चलते इसे स्पेसबग भी कहा जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर,1 जवान घायल

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बट्टाल सेक्टर में मंगलवार (23 जुलाई) सुबह करीब 3 बजे आर्मी-आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। सेना की ओर बताया गया कि कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। बीएसएफ के

सूत्रों के मुताबिक, पुंछ के कृष्ण घाटी बेल्ट से कुछ आतंकी बट्टाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवानों को आतंकियों के मूवमेंट की सूचना मिल गई थी। सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें रोका। हालांकि, आतंकियों के घायल होने या मारे जाने की सूचना अभी नहीं मिली है। गोलीबारी में घायल हुए जवान को अस्पताल पहुंचाया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू में यह 24 घंटे में दूसरा हमला है।

चुनिंदा मामलों में ही जमानत पर रोक लगे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट के पास बेल ऑर्डर पर स्टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन यह स्टे सिर्फ असामान्य मामलों और असाधारण परिस्थितियों में ही लगाना चाहिए। जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह टिप्पणी मनी

लॉन्ड्रिंग के आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। दरअसल, खुराना को ईडी ने 2023 में गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट से जून 2023 में बेल मिल गई थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बेल ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि एक साल तक एक शख्स बिना किसी कारण के सड़ रहा है।

पिनाका, ब्रह्मोस...

भारतीय हथियारों की दीवानी हुई दुनिया

विश्व के टॉप निर्यातकों में हुआ शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनियाभर में तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत के हथियारों का निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा इकनॉमिक सर्वे से खुलासा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश अब हथियारों के निर्यात में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। भारत ने करीब 85 देशों को ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट और तोपें निर्यात की हैं। भारत बड़े पैमाने पर तोप के गोलों का भी निर्यात कर रहा है। भारत से हथियार खरीदने वाले देशों में आर्मेनिया और फिलीपीन्स जैसे देश शामिल हैं जो बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा इटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, यूएई, फिलीपीन्स, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजरायल, स्पेन चिली भी शामिल हैं। भारत के इकनॉमिक सर्वे 2024 के मुताबिक भारत का हथियार उत्पादन साल 2017 के वित्तीय वर्ष में 74,054 करोड़ था जो साल 2023 में बढ़कर अब 1,08,684 करोड़ पहुंच गया है। इससे हथियारों का निर्यात काफी बढ़ गया है। साल 2015 से 2019 के बीच में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था लेकिन अब वह टॉप 25 हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। सबसे बड़े हथियार निर्यात में अहम भूमिका निभाई है।

प.बंगाल के साउथ 24 परगना में मिली गुप्त सुरंग

गवर्नर बोले-बांग्लादेश बॉर्डर के पास टनल मिलना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के एक घर में पुलिस को एक सुरंग मिली थी। यह सुरंग बांग्लादेश की बॉर्डर के करीब है। इसे लेकर गवर्नर आनंद बोस ने ममता सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं। गवर्नर ने कहा है कि बॉर्डर के पास के घर में सुरंग निकलना देश के लिए खतरा है। ममता बनर्जी सरकार को मजबूत और निष्पक्ष कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत है। दरअसल, 15 जुलाई को पुलिस ने सद्दाम नाम के शख्स के घर पर छापा मारा था। सद्दाम नकली सोने के मूर्ति का डीलर है। उसके घर पर मिली 40 मीटर लंबी सुरंग नहर की ओर निकलती है। इस नहर से नाव के सहारे मतला नदी तक पहुंचा जा सकता है, जहां से बांग्लादेश सीमा को पार किया जा सकता है। पुलिस का मानना है कि सद्दाम ने सुरंग का इस्तेमाल छापेमारी के दौरान भागने के लिए भी किया था।

मध्य दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक की करंट लगने से मौत

नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के पटेल नगर में भारी वर्षा के बाद कथित रूप से करंट लगने से सिविल सेवा परीक्षा के 26 वर्षीय एक अभ्यर्थी की मौत हो गयी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (मध्य) एम हर्षवर्द्धन ने कहा, ''सोमवार को दो बजकर 43 मिनट पर रणजीत नगर थाने में सूचना आयी कि पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक पावर जिम के पास एक व्यक्ति बिजली का करंट लगने से लोहे के गेट से चिपक गया।'' उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने पाया कि लोहे के गेट में बिजली का करंट आ जाने से यह व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया और सड़क पर पानी भी भरा हुआ था। उन्होंने कहा, ''उस व्यक्ति को राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।'' पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस व्यक्ति की पहचान नीलेश राय के रूप में की गयी है जो पटेल नगर में किराये के एक मकान में रहकर सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस घटना के सिलसिले में रणजीत नगर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है और फोरेंसिक टीम मौके पर भेजी गयी है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, नौ महिलाओ समेत 20 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और सरकारी योजनाओं के तहत ऋण मुहैया कराने के बहाने लोगों को ठगने के आरोप में नौ महिलाओं सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने कहा, 'अनुमान है कि 400 से अधिक पीड़ित कॉल सेंटर की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, जिसके कारण कुल 40 लाख रुपये की ठगी हुई है। पुलिस पहले ही देश भर में 50 से अधिक पीड़ितों की पहचान कर चुकी है।' डीसीपी ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली के लाडो सराय इलाके से संचालित यह फर्जी कॉल सेंटर सरकारी योजनाओं के तहत लोन दिलाने के नाम पर लोगों को ठगता था। डीसीपी ने बताया कि वे एकत्रित किए गए विवरणों का इस्तेमाल अपने खातों में पैसे हस्तांतरित करने के लिए करते थे। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को नौ महिला टेली–कॉलर्स समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया। डीसीपी ने कहा, 'उनके पास से कुल 32 मोबाइल फोन, 48 फर्जी सिम कार्ड, चार लैपटॉप और 23 बैंक खाते जब्त किए गए। मामले की आगे की जांच जारी है।'

दिल्ली के करोल बाग में दुकान में आग लगी

नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के करोल बाग इलाके में मंगलवार दोपहर को एक दुकान में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। डीएफएस अधिकारी ने कहा, ''हमें अपराह्न दो बजकर 40 मिनट पर करोल बाग में एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली।'' अधिकारी ने कहा, ''तीन दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।'' किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं मिली है।

फरार चल रहे आजीवन कारावास के दोषी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरार चल रहे आजीवन कारावास के दोषी को गिरफ्तार किया है। वह 2023 से फरार था। आरोपित की पहचान कमल कुमार (40) के रूप में की गई है। आरोपित को पुलिस ने उप्र के सहारनपुर से एक टेंट की दुकान से गिरफ्तार किया है। आरोपित ने पड़ोसी से हुए झगड़े का बदला लेने के लिए उसकी 8 साल की बेटी को किडनैप करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। कोर्ट के आदेशों पर आरोपित कमल कुमार को 25 मई 2021 में 90 दिन की पैरोल मिली थी। इसको 24 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था। इस अवधि के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर आरोपित को कोर्ट के सामने सरेंडर करना था, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से बचते हुए फरार हो गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कमल कुमार बार–बार अपने ठिकाने बदलता रहा था। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल के मुताबिक, फरवरी 2002 में दक्षिणपुरी इलाके रहने वाले कमल कुमार का झगड़ा किसी मामले को लेकर अपने पड़ोसी बृजेश कुमार से हो गया था। झगड़े के बाद आरोपित कमल ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 19 मार्च, 2002 को बृजेश की 8 साल की बेटी को अगवा कर लिया था। इसके बाद उसने उसके चेहरे पर एक भारी पत्थर मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके खिलाफ अंबेडकर नगर थाने में आरोपित कमल के खिलाफ आईपीसी की धारा 363/354/302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। साल 2006 में उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

करंट लगने से छात्र की मौत

नई दिल्ली। मध्य जिले के अंतर्गत रंजीत नगर इलाके में एक यूपीएससी स्टूडेंट की बारिश के बाद सड़क पर करंट लगने से दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। छात्र को कंपाउंड के एंट्री गेट पर जमा पानी में करंट लगा। गेट के साथ ही एक बिजली का खंभा लगा है जिस पर बिजली और अन्य के तारों का जाल बुना देखा जा सकता है। इस दर्दनाक हादसे पर दिल्ली से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर कर दुःख जताया है। मालीवाल ने लिखा 'एक्स' पर लिखा, दिल्ली के पटेल नगर में एक यूपीएससी छात्र की बारिश के बाद सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई। ये कोई दुर्घटना नहीं, सरकारी सिस्टम की नाकामी द्वारा की गई हत्या है। आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। उस बच्चे के मां–बाप को क्या जवाब देंगे। सड़क पर चलने से मौत हो गई, सॉरी? इस घटना में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए एवं सभी जिम्मेदारों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।' बताया जाता है कि इस मामले पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया। रणजीत नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य जिले के डीसीपी एम. हर्ष वर्धन ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतक की पहचान नीलेश राय के रूप में हुई है।

मानहानि मामले में आप नेता आतिशी को जमानत

नई दिल्ली, । मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी को मंगलवार को अदालत ने जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल की अदालत ने आतिशी के समन के अनुपालन में पेश होने के बाद उन्हें 20 हजार रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी। भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के उस बयान के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें उन्होंने भाजपा द्वारा आप नेताओं को रुपये का लालच देकर पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क करने की बात कही थी। अदालत ने 28 मई को शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब करने का अनुरोध ठुकरा दिया था। हालांकि, कोर्ट ने आतिशी को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था। अदालत दस्तावेजों की जांच और आरोप तय करने के संबंध में दलीलों के लिए आठ अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई करेगी।

स्क्रैप कारोबारी से साठ लाख ठगे वाला बदमाश दबोचा

नई दिल्ली, 23 जुलाई (वेब वार्ता)। लूट की झूठी कहानी बता स्क्रैप कारोबारी के साठ लाख रुपये उड़ाने वाले बदमाश को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। रोहिणी इलाके से पकड़ा गया आरोपी पुलिस को करीब डेढ़ साल से चकमा दे रहा था। आरोपी की पहचान मंगल तिवारी उर्फ सुनील के रूप में हुई है। मामले की जांच में जुटी पुलिस अब चोरी की रकम से खरीदे गए सामान बरामद करने के प्रयास कर रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक एक जनवरी 2023 को पीतमपुरा निवासी विरेंद्र गर्ग ने इस संबंध में शिकायत दी थी। पीड़ित ने बताया कि उनका लोहे के स्क्रैप का कारोबार है। गत 31 दिसंबर 2022 को विरेंद्र ने अपने एक कर्मी मंगल को घर एक बैग दिया। उसमें साठ लाख रुपये थे। 31 दिसंबर को मंगल कारोबारी के घर पर रुका। अगले दिन उसे रुपये लेकर विरेंद्र के दोस्त के पास जाना था। इस बीच शाम करीब पांच बजे मंगल ने कॉल कर पैसे लूट जाने की बात कही। इस बात पर विरेंद्र ने उससे ऑफिस आकर पुलिस को शिकायत करने के लिए कहा तो वह पहले तो आना-कानी करने लगा। फिर वह गायब हो गया। बहरहाल रूप नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की लेकिन आरोपी का कुछ पता नहीं चल सका। इस बीच क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि आरोपी रोहिणी इलाके में छिपकर रह रहा है तो उसे दबोच लिया गया। जांच आगे बढ़ी तो यह पता चला कि आरोपी ने कारोबारी की इस रकम से मकान, कार और जेवरात खरीदे। इसके बाद वह लगातार अपने मकान भी बदलता रहा।

दिल्ली को केंद्रीय करों के उसके हिस्से के रूप में एक पैसा नहीं दिया गया: आतिशी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले केंद्र को करों के रूप में 2.32 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने के बावजूद केंद्रीय बजट के केंद्रीय करों में दिल्ली को उसके हिस्से के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला है। आतिशी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए बजटीय आवंटन की मांग की थी लेकिन उसे केंद्र से एक भी पैसा नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी (आप) की नेता ने कहा, ''दिल्ली देश की वृद्धि का इंजन है। वह केंद्र को आयकर के रूप में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक और केंद्रीय जीएसटी के रूप में 25,000 करोड़ रुपये का भुगतान करती है। केंद्र को 2.32 लाख करोड़ रुपये का कर देने के बावजूद दिल्ली महज 20,000 करोड़ रुपये मांग रही थी जो कि केंद्रीय बजट का सिर्फ 0.4 प्रतिशत है। लेकिन केंद्र करों में अपने हिस्से के रूप में या एमसीडी को कोई पैसा नहीं दिया गया है। उन्होंने भाजपा को ''केंद्र में उसकी सरकार द्वारा पेश किए पिछले 11 बजट में दिल्ली के लिए किया गया एक भी काम दिखाने'' की चुनौती दी। आतिशी ने कहा, ''पिछले 11 वर्ष में केंद्र में भाजपा सरकार ने दिल्ली के लिए एक भी काम नहीं किया। केंद्रीय बजट ने दिल्ली के लोगों को दिखा दिया है कि भाजपा ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए यह बजट पेश किया और यह देश के लोगों के लिए नहीं है।''

बजट 2024 में रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री पैकेज का ऐलान, युवाओं ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री पैकेज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (ईपीएफओ) पर आधारित होगी। उन्होंने पांच योजनाओं के लिए बजट में 2 लाख करोड़ के आवंटन का ऐलान किया। वहीं, इस बजट को युवाओं के लिए खास बताया गया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बजट में पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा दिया गया है। संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए तीन किस्तों में जारी किया जाएगा। इस बजट में प्रधानमंत्री पैकेज की बात कही गई है। रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत तीन योजनाएं घोषित की जाएगी। वहीं, प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा के बाद युवाओं ने क्या आइए जानते हैं...

बजट पर बात करते हुए मोहमद सारिक ने कहा कि बजट के दौरान प्रधानमंत्री पैकेज का ऐलान किया गया है, जो अच्छा है। उसमें पहली बार रोजगार पाने वाले को ?15000 तक मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं। आज के समय बेरोजगारी चरण पर है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाओ तो आसानी से जॉब नहीं मिलेगी। कंपनी कर्मचारी हायर करने की जगह उन्हें निकाल रही है। मोदी सरकार को देखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं।

ग्रेजुएशन करके रोजगार की तलाश में बैठे अंकित कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जो पैकेज लॉन्च किया गया है, उसमें बताया गया कि रोजगार देने वाले और रोजगार मिलने वाले दोनों लोगों को फायदा होगा। अंकित का कहना है कि एक करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन सिर्फ एक करोड़ लोगों से क्या होगा। दिल्ली की आबादी ही ढाई तीन करोड़ है। इतने सारे युवा बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी देनी चाहिए। एक करोड़ लोगों को ट्रेंड करने से कुछ नहीं होगा, यह एक लॉलीपॉप की तरह है।

जीटीबी अस्पताल गोलीकांड का मास्टरमाइंड 'समीर उर्फ बाबा' साथी के साथ ऋषिकेश से गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल गोलीकांड में फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाशिम बाबा गैंग के मेंबर और गोलीकांड के मास्टरमाइंड समीर उर्फ बाबा (22) और राहुल सिंह उर्फ राहुल खटीक (33) को ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने दो अन्य कुख्यात अपराधियों को मयूर विहार इलाके से दबोचा है।

स्पेशल सेल नई दिल्ली रेंज की डीसीपी प्रतीक्षा गोदारा के मुताबिक, जीटीबी अस्पताल में एक मरीज की हत्या मामले की पूरी साजिश रचने वाले आरोपी समीर उर्फ बाबा और उसके तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया है। समीर नौवीं कक्षा तक पढ़ा है। उसने आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया था। साल 2019 में उसका लोकल क्रिमिनल के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके कारण दुश्मनी बढ़ गई।

इसके बाद समीर आपराधिक तत्वों के संपर्क में आ गया और क्राइम करना शुरू कर दिया। 13 जून 2024 को आरोपी समीर और गिरोह के 5 अन्य सदस्यों ने ही अपने प्रतिद्वंदी वसीम अस्मत को खत्म करने के लिए पूरा जाल बिछाया। उस समय वेलकम इलाके में वसीम अस्मत पर ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाई थी। घायल होने के बाद उसको जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस हमले में बच चुके वसीम को उसने फिर से जीटीबी अस्पताल में मारने की पूरी योजना बनाई।

जानकारी के अनुसार, इस बार आरोपी समीर अस्पताल नहीं गया, क्योंकि उसे लगता था कि वाशिम अस्मत या उसका भाई उसको पहचान लेगा। तब उसने अपने साथियों को वसीम को मारने के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा। लेकिन एक ही वार्ड में दो कमरे होने की वजह से आरोपी के साथियों ने गलती से एक

मासूम मरीज की हत्या कर दी। मृतक की पहचान रियाजुद्दीन, खजूरी खास के रूप में हुई थी। इस हमले के बाद से पुलिस समीर व उसके साथियों की तलाश में जुटी थी।

डीसीपी प्रतीक्षा गोदारा के मुताबिक, शुरुआत में पता चला कि राहुल सिंह उर्फ राहुल खटीक और समीर दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। आगे टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों के आधार पर इन दोनों की मूमेंट उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास मिली। पुलिस ने आरोपियों का पीछा कर 19 जुलाई को दबोच लिया। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद दो अन्य फरार आरोपी मुकेश उर्फ सचिन उर्फ गोलू और सुहैल उर्फ तौहिद उर्फ शूटर को 20 जुलाई की रात मयूर विहार से दबोच गया। इन सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग थानों में अनेक मामले दर्ज हैं।

सरकारी योजना के तहत लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकारी योजना के तहत लोन देने के नाम पर देशभर के 400 से अधिक लोगों से चीटिंग करने वाले गैंग का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 9 महिला सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह लोग फर्जी कॉल सेंटर खोलकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के लोगों से ठगी कर चुके हैं। डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली कि साकेत के लाडो सराय इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। सूचना के बाद छापेमारी के लिए एक टीम बनाई गई। वहीं, छापेमारी के दौरान साउथ

डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने 9 महिला समेत 11 टेली कॉलर को पकड़ा। पुलिस पूछताछ में पता चला कि कॉल सेंटर कर्मी संभावित ग्राहकों के मोबाइल नंबरों पर फर्जी कॉल करने और उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत गलत लोन देने की पेशकश करते थे। अभी तक की जांच में करीब 40 लाख से अधिक की ठगी का पता चला है। यह लोग सरकारी लोन देने के नाम पर पीड़ित के बैंक का सारा डिटेल लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकेश, राहुल, राजेश, दीपक, राहुल, राज पांडे, मो. शाहकार, मो. इमाम और अंकुर धुरिया के रूप में हुई है। वहीं, इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड कालकाजी निवासी विकेश है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि यह लोग फर्जी आईडी से पहले फर्जी सिम लेते थे। फिर ग्राहकों को सरकारी योजना के तहत लोन देने का झांसा देते थे। फिर उन्हें 100 रुपए का ऑनलाइन टोकन भुगतान करने को कहते थे। जब पीड़ित भुगतान करता तो त्रुटि आ जाता था। फिर पीड़ित को कटौती की गई राशि का मैसेज साझा करने को कहते थे। उसके बाद पीड़ित के अकाउंट का सारा डिटेल उनके पास आ जाता था। फिर वह पीड़ित को पुन प्रयास करने के लिए कहते थे। फिर उनके बैंक खाते में 100 रुपए के बदले खाते में रखा सारा अमाउंट ठगी कर लेते थे।

शाहदरा एएटीएस ने पकड़ा अवैध शराब से लदा मिनी ट्रक, 4500 क्वार्टर लिकर बरामद

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) टीम ने एक कुख्यात शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। अवैध लिकर सप्लायर से टीम ने 90 कार्टन यानी 4500 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की है। आरोपी की पहचान विक्की गुप्ता उर्फ विमल के रूप में की गई है जोकि शाहदरा के मोहन पार्क इलाके का रहने वाला है और पिछले 25 सालों से अवैध शराब की सप्लाई के गोरखधंधे में संलिप्त रहा है। इससे पहले उसके सहयोगी मोनू उर्फ गोलू से 15 जुलाई को 2500 क्वार्टर शराब बरामद की गई थी।

केंद्रीय बजट 2024: जानिए मोदी सरकार 3.0 के बजट पर क्या बोले दिल्ली के व्यापारी?

नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज करीब 2 घंटे लोकसभा में बजट भाषण पढ़ा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट पर देश भर के व्यापारियों को काफी उम्मीद थी। जैसे इनकम टैक्स, बैंक लोन, पेट्रोल डीजल की कीमतों और जीएसटी में कोई रियायत दी जाएगी। ऐसे में आइये जानते हैं इस बार के आम बजट से दिल्ली के व्यापारी कितने संतुष्ट हैं...

भारतीय व्यापार मंडल के महामंत्री हेमंत गुप्ता का मानना है कि सरकार ने अपने बजट 2024-2025 में खाद्य, तेल और तलहनों पर अधिक खर्च करने की बात कही है। यह अच्छी बात है। इसके उत्पादन पर खर्च बढ़ेगा तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। लेकिन व्यापारियों की मांग थी कि तेल पर वसूली जाने वाली आयात ड्यूटी को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर सरकार इस बात का ध्यान रखती तो देश के किसानों को घरेलू उत्पाद को सहायता मिलती। साथ ही इस बार भी बजट में इनकम टैक्स में कुछ खास रियायत नहीं दी गई। वेतनभोगी कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50, 000 से बढ़ाकर 75, 000 किया गया है। वहीं इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की बात कही गई है। अब देखना होगा सरकार पुरानी दिल्ली के बाज़ारों में किस तरह का सुधार करती है।

सरोजिनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान अशोक रंधावा ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट से छोटे दुकानदारों को काफी उम्मीदें थी। लेकिन इस बार के बजट से केवल निराशा हाथ लगी है। उम्मीद थी कि कपड़ों की बिक्री में तस्ज्ञ रेट पर कुछ छूट मिलेगी। इसके अलावा यह भी उम्मीद थी छोटे दुकानदारों को स्वास्थ्य संबंधी बीमा की सुविधा और बैंक से लोन लेने में कुछ रियायत दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह बजट सुनने में अच्छा है लेकिन जमीनी स्तर पर ठीक नहीं है। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री बोलीं महंगाई कम हुई है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है।

कश्मीरी गेट स्थित ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनय नारंग ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी मोटर पार्ट्स व्यापारी निराश हुए हैं। इस बार इनकम टैक्स में कुछ फेर बदल किए गए हैं, लेकिन इससे किसी भी व्यापारी की कोई राहत नहीं मिली है। इससे केवल नौकरीपेशा लोगों को फायदा होगा। वहीं, एमएसएमई में बैंक को ज्यादा ताकत दी गयी है, ताकि बैंक छोटे व्यापारियों को अच्छे से लोन मुहिया करा सके। लेकिन इसमें ब्याज दर का कही भी जिक्र नहीं है। यह बजट एक लोली पॉप बजट है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बजट में व्यापारियों को दरकिनार किया गया है।

ऑल इंडिया मोटर एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने बताया कि बजट 2024 में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की समस्याओं और आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना विरोध के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की आवाज न तो सुनी जाती है और न ही उसका उल्लेख होता है। इस प्रकार की उपेक्षा से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निराशा का माहौल बन गया है। सरकार को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की समस्याओं पर ध्यान दें। दिल्ली प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रेसिडेंट चंद्रभूषण गुप्ता ने बताया कि बजट में सरकार ने एमएसएमई पर जोर दिया है। घोषणाओं के धरातल पर उतरने और उसके प्रभाव को समझने में समय लगेगा। अब मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ये निश्चित तौर पर सकारात्मक कदम है। खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए बिजनेस लिमिट को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जा रहा है। एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों को बेचने में पीपीपी मोड में काम होगा। ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित होने का फायदा मिलेगा।

चांदनी चौक में स्थित कूचा महाजनी में कार्यरत ऑल बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंगल ने बताया कि आज के बजट में ज्वेलरी इंडस्ट्री की काफी पुरानी मांग को पूरा किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला ने सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी से 6 फीसदी किया है। इससे ज्वेलरी के गैरकानूनी व्यापार पर लगाम लगेगी। साथ ही जो व्यापारी ईमानदारी से सोना बेचना चाहते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा।

यह भारत का बजट है, पीएम मोदी ने अपना वादा निभाया : मनोज तिवारी

नई दिल्ली। उत्तर–पूर्व दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज तिवारी ने इसे भारत का बजट करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मनोज तिवारी ने कहा, 'बजट में देश के युवाओं, देश के किसान के लिए बहुत कुछ है, छात्रों के लिए भी पहली बार शिक्षा लोन 10 लाख रुपये कर दिया गया है। मुद्रा लोन भी 10 लाख से 20 लाख रुपये कर दिया गया है। तीन करोड़ गरीबों के लिए नया घर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, उसको निभाया है।' उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए 1500 करोड़ पैकेज, विशाखापट्टनम से चेन्नई कॉरिडोर बनाने के लिए उत्तर से दक्षिण तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए विशेष पैकेज है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंसर के रोगियों के लिए कई दवाओं से कस्टम हटा दिया गया है। विपक्ष द्वारा इस बजट को 'आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट' कहने पर, मनोज तिवारी ने कहा कि युवाओं के लिए पहली नौकरी पर सरकार की तरफ से स्पेशल पैकेज का प्रावधान हुआ है। राहुल गांधी को ध्यान से देखना चाहिए कि मोदी सरकार ने युवाओं को क्या उपहार दिया है। बिहार, असम की बाढ़ के लिए बजट है, इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की लैंडस्लाइड को भी शामिल किया गया है। यह सही मायने में भारत का बजट है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने मोदी सरकार के बजट की प्रशंसा की और कहा कि भारत सरकार ने बजट में बिहार को विशेष पैकेज से ज्यादा दे दिया है। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए विशेष पैकेज पर विपक्ष हमलावर है। केंद्रीय बजट पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह 'कुर्सी बचाओ' बजट है। उन्होंने कहा कि ये बजट एनडीए के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ रखने के लिए है, ये बजट देश के लिए नहीं है।

केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को मिले 11400 करोड़

नई दिल्ली, । दिल्ली पुलिस को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए केंद्रीय बजट में करीब 11 400.81 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के संशोधित बजट की राशि 12,128.83 करोड़ रुपये की तुलना में 728.02 करोड़ कम है। केंद्र सरकार ने स्थापना–संबंधी व्यय के लिए राजस्व श्रेणी के तहत 10, 291.28 करोड़ रुपये और पूंजी श्रेणी के लिए 1109.53 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पूंजी श्रेणी के तहत दी गई धनराशि का उपयोग नई इमारतों के निर्माण, वाहनों, हथियारों और लंबी अवधि के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य सामान खरीदने में किया जाता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि यह राशि हाउसिंग स्कीम में इस्तेमाल की जाएगी तो इससे आवासीय और कार्यालय से जुड़ी समस्या कम होगी। इस बजट से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने और जांच को वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित करने में मदद मिलेगी। बजट में फोरेंसिक पर जोर दिया गया है। वहीं, पुलिसकर्मियों के लिए हाउसिंग स्कीम पर भी जोर देने से इनकी आवासीय समस्याएं दूर होगी। अशोक चांद, पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर, दिल्ली पुलिस.

दिल्ली के किसानों को नहीं मिली राहत : डॉ. नरेश कुमार

नई दिल्ली। राजधानी के किसानों के लिए बजट निराशा भरा रहा है। किसान नेता डॉ. नरेश कुमार ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि फसल की लागत का मूल्य मिलेगा और समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों को कर्ज माफ होने, शून्य ब्याज दर पर कर्ज मिलने के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाए जाने की भी उम्मीद थी। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सस्ते बीज, खाद, कीटनाशक आदि पर भी सरकार को राहत देनी चाहिए थी। सरकार ने बजट में नेचुरल फार्मिंग की बात तो की है, लेकिन ऐसी खेती में उत्पादन कम होता है, इसलिए सरकार को इसकी भरपाई का भी प्रावधान बजट में करना चाहिए था।

आजीवन कारावास का दोषी पैरोल जंपर सहारनपुर से गिरफ्तार, मासूम की हत्या में काट रहा आजीवन कैद की सजा

नई दिल्ली, । दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आजीवन कारावास के दोषी पैरोल जंपर को गिरफ्तार किया है। वह 2023 से फरार था। आरोपी की पहचान कमल कुमार (40) दक्षिणपुरी, दिल्ली के रूप में की गई है, जिसको यूपी के सहारनपुर से एक टेंट की दुकान से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पड़ोसी से हुए झगड़े का बदला लेने के लिए उसकी 8 साल की बेटी को किडनैप करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। कोर्ट के आदेशों पर आरोपी कमल कुमार को 25 मई 2021 में 90 दिन की पैरोल म?िली थी। इसको 24 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था। इस अवध? के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर आरोपी को कोर्ट के सामने सरेंडर करना था, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से बचते हुए फरार हो गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कमल कुमार बार–बार अपने ठिकाने बदलता रहा था। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक, फरवरी 2002 में दक्ष?िणपुरी इलाके रहने वाले कमल कुमार का झगड़ा क?िसी मामले को लेकर अपने पड़ोसी बृजेश कुमार से हो गया था। झगड़े के बाद आरोपी कमल ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 19 मार्च, 2002 को बृजेश की 8 साल की बेटी को अगवा कर लिया था। इसके बाद उसने उसके चेहरे पर एक भारी पत्थर फेंक कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके खिलाफ अंबेडकर नगर थाने में आरोपी कमल के ख?िलाफ आईपीसी की धारा 363/354/302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। साल 2006 में उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

संक्षिप्त समाचार

दुस्साहसः फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से एक लाख की लूट

वाराणसी , एजेंसी। वाराणसी के शिवपुर थाना के कानूडीह इलाके में मंगलवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार कर फाइनेंस कंपनी के एक स्टाफ से एक लाख दो हजार रुपये लूट लिए। फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी भदोही के औराई का रहने वाला योगेश बताया गया है। योगेश के दाएं पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि योगेश कानूडीह इलाके में समूह की महिलाओं के साथ बैठक कर रहा था। उसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाश आए और योगेश के दाएं पैर में गोली मार कर पैसे से भरा बैग छीन कर रिंग रोड की ओर भाग निकले। घटना की सूचना पाकर शिवपुर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची है।

दर्दनाकः गड्ढे में पलटा ट्रक, केबिन में फंसे चालक की तड़पकर हुई मौत

मिर्जापुर , एजेंसी। मिर्जापुर के जिगना विन्ध्याचल थाना क्षेत्र के गैपुरा लालगंज मार्ग पर मंगलवार की सुबह पांच बजे सोनभद्र से प्रयागराज राखड़ लेकर जा रहा ट्रक पलट जाने से चालक की दर्दनाक मौत हो गई। केबिन काटकर उसका शव निकाला गया। खलासी किसी तरह बाहर निकला जिसकी हालत गम्भीर होने पर मंडलीय अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, चालक आदित्य कुमार (25) परिचालक दीपक (27) के साथ विन्ध्यनगर से राखड़ लाद कर प्रयागराज सहसो जा रहा था। लालगंज से गैपुरा आते समय विजयपुर पहाड़ी की ढलान पर ट्रक पलट कर लगभग 30 फीट नीचे चला गया। परिचालक तो किसी तरह बाहर आ गया। चालक को निकालने में पुलिस व ग्रामीण घंटों जुटी रही। बाद में चालक की मौत हो गई। ट्रक का केबिन काटकर उसका शव निकाला गया।

पति- पत्नी के रहते मुस्लिम महिला को लाया घर, केस दर्ज

गोरखपुर , एजेंसी। शाहपुर इलाके के हड़हवा फाटक निवासी महिला ने अपने पति संजय पर दूसरे समुदाय की महिला को घर में लाकर रखने का आरोप लगाया है। पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर रविवार की रात शाहपुर पुलिस ने पति, सास और देवर के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, शाहपुर के हड़हवा फाटक निवासिनी एक महिला की शादी सात वर्ष पहले उसी मोहल्ले में रोहित से हुई थी। आरोप है कि रोहित तीन महीना पहले एक मुस्लिम महिला को लेकर घर छोड़कर भाग गया था। रोहित उस महिला के प्रेम संबंध में पड़ गया था। शनिवार को उस महिला को घर में लेकर आया तो पहली पत्नी ने विरोध किया। तब पति समेत परिजन उसे मारने-पीटने लगे। जिसके बाद महिला ने रविवार की सुबह शाहपुर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया।

सेवानिवृत्त दरोगा के बेटे ने किया ऐसा खेल, इस तरह बनाई करोड़ों की संपत्ति

आगरा , एजेंसी। आगरा में फर्जी आधार कार्ड, पैनकार्ड के सहारे सहारनपुर की आईसीआईसीआई बैंक से 4.60 करोड़ रुपये का लोन लेने और उसे हड़पने का मास्टरमाइंड अरुण पाराशर सेवानिवृत्त दरोगा का बेटा है। वह ठगी की रकम से करोड़ों की संपत्ति बना चुका है।

उसके साथियों ने भी मकान, दुकान और गाड़ी खरीद ली है। एसटीएफ गिरोह में शामिल अन्य के बारे में भी पता कर रही है। नोएडा एसटीएफ और सहारनपुर शनिवार रात को नगला अजीता निवासी अरुण पाराशर, कृष्णा कॉलोनी निवासी शुभम तिवारी और ककरैठा निवासी अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार किया था। उन्हें सहारनपुर पुलिस के हवाले किया गया। उन पर आरोप है कि सहारनपुर में बैंक से फर्जी दस्तावेजों की मदद से 4.60 करोड़ का लोन लेकर हड़प लिया गया।

पुलिस ने आरोपी अरुण पाराशर से पूछताछ की। पता चला कि वह पूर्व में भी पकड़ा गया था। उसके पिता शिवनाथ पाराशर पुलिस में दरोगा थे। सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस कारण ही अरुण रुतबा बनाकर रखता है। अपनी गाड़ी में दरोगा की कैप को डैशबोर्ड पर रखता है, जिससे पुलिस चेकिंग में न रोक सके। अन्य लोग भी उससे डर जाएं।

दुकानों से हटाए जाने लगे नाम...

कांवड़ मार्ग के दुकानदारों ने उतारे फ्लैक्स

मुजफ्फरनगर , एजेंसी। मुजफ्फरनगर में खाद्य पदार्थ की दुकानों पर नाम प्रदर्शित करने के मामले में सुप्रीमकोर्ट की अंतरिम रोक का असर कांवड़ मार्ग पर देखने को मिला। अधिकतर दुकानदारों ने नाम वाले फ्लैक्स उतार दिए हैं। सोमवार को सुप्रीमकोर्ट के आदेश का असर पुरकाजी से खतौली के भंगेला तक नजर आया।

पुरकाजी बाईपास, छपार, रामपुर तिराहा के ढाबों से फ्लैक्स दुकानदारों ने खुद ही हटा दिए हैं। शहर में रुड़की रोड पर मिठाई की दुकानों पर लगे नाम प्रदर्शित करने वाले पोस्टर भी हटाए गए। भगत सिंह रोड, बुढ़ाना रोड और खतौली में बाईपास के ढाबों से भी नाम गायब नजर आने लगे हैं।

दुकानदार नदीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत देने वाला है। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, अब सर्वसमाज को मिलकर कांवड़ यात्रा में सहयोग कर सकुशल संपन्न कराना चाहिए। गौरतलब है कि जिले की सीमा में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले 75 ढाबों और अन्य दुकानों पर नाम प्रदर्शित किए गए थे। एसएसपी अभिषेक सिंह का कहना था कि ढाबा संचालकों ने स्वेच्छा से नाम प्रदर्शित कर लिए हैं।

इस तरह नाम के मामले ने पकड़ा तूलः पानीपत-खटीमा हाईवे पर योग साधना यशवीर आश्रम बघरा के संचालक यशवीर महाराज ने अन्य धर्म गुरुओं के साथ 24 जून को पुलिस-प्रशासन के साथ बैठक की थी, जिसमें नाम लिखवाने का मुद्दा उठा था।

कौशल विकास राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने पांच जुलाई को अधिकारियों के साथ विकास भवन में बैठक के दौरान ढाबा मालिक और संचालक का नाम लिखने और हिंदू देवी-देवताओं के नाम ना रखने की बात कही थी।

एसएसपी अभिषेक सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा था कि कांवड मार्ग के सभी होटल, ढ़ाबे और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर सभी मालिक, संचालक और कर्मचारियों का नाम अंकित करें, ताकि भ्रम पैदा ना हो।

-एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट इस मामले में 17 जुलाई को नाराजगी जताई। 18 जुलाई को पूर्व सीएम अखिलेश यादव और पूर्व सीएम मायावती ने विरोध किया था।

- रालोद अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने 21 जुलाई को मुजफ्फरनगर में सरकार के फैसले पर असहमति जताई थी।

फैसला निराशाजनक, न्यायालय पर भरोसा : यशवीर महाराज

फैसले के बाद यशवीर महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नेम प्लेट लगाने पर जो दिशा निर्देश आया है, वह निराशाजनक है। लेकिन हमें न्यायालय पर विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। न्यायालय ने अभी एक पक्ष को सुना है। हिंदू समाज मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगा। हमें उम्मीद है आने वाली सुनवाई में हमें इस धोखाधड़ी के नाम के षडयंत्र से राहत मिलेगी। होटल ढाबे खाद्य पदार्थ की दुकान पर लगे हिन्दू देवी देवताओं के नाम के प्रयोग से छुटकारा मिलेगा।

कांवड़ियों की भावनाओं का रहना चाहिए सम्मान :अग्रवाल

कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ियों की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। नाम के फेर में भावनाओं से खिलवाड़ सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आना चाहिए, जिससे कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

पीड़ित से कार्रवाई के नाम पर वसूले 17 हजार

आरोपी सिपाही पर रिपोर्टजनिलंबित, सीओ को सौंपी जांच

हरदोई , एजेंसी। हरदोई जिले में मल्लावां कस्बे के मोहल्ला बंदीपुर में हुई मारपीट के मामले में गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजने के नाम पर सिपाही ने 17 हजार रुपये पीड़ित से वसूल लिए। सोमवार को पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई। एसपी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच कराई और प्रथम दृष्टया मामला सही मिलने पर आरोपी सिपाही के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। आरोपी सिपाही को निलंबित भी कर दिया गया है। मल्लावां कस्बे के मोहल्ला बंदीपुर निवासी ईदुल हसन के मकान जान वाले सार्वजनिक मार्ग प र कुछ लोगों ने दो माह से गिट्टी डाल रखी थी। शनिवार को ईदुल ने मिट्टी हटाने के लिए दिलशाद खां से कहा था। इससे नाराज होकर दिलशाद ने अपने परिजनों और परिचितों के साथ मिलकर ईदुल के घर पर हमला बोल दिया था। घटना में ईदुल, उसके दो भाई और पिता घायल हो गए थे। घटना की रिपोर्ट भी मल्लावां कोतवाली में दर्ज की गई थी। ईदुल का आरोप है कि घटना की जानकारी मल्लावां कोतवाली में दील गई थी, लेकिन शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रीय सिपाही सोनू फौजदार ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजने के नाम पर ईदुल से 17 हजार रुपये वसूल लिए गए।

कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का आरोपी है सोनू सिंह, जेल से कचहरी आया था पेशी पर- फरार

गोरखपुर , एजेंसी। दीवानी कचहरी में सोमवार को पेशी पर आया बंदी सोनू सिंह सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। वह भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के आरोप में जेल में बंद था।

कचहरी लॉकअप में शाम को गिनती के समय प्रभारी को जानकारी हुई तो इसकी सूचना अधिकारियों के साथ ही कैंट पुलिस को दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कचहरी पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

जानकारी के अनुसार, सिकरीगंज क्षेत्र के रहने वाले फरार बंदी सोनू सिंह की बस्ती जिले में ससुराल है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस तलाश कर रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से लगायत शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही बाहर जाने वाले वाहनों की भी पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।

हत्या कर कुल्हाड़ी लेकर बैठा था आरोपीः सिकरीगंज के बारीगांव में रहने वाले सोनू सिंह ने आठ जनवरी 2021 को रुपये के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर बड़े भाई बालेंद्र सिंह की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी कुल्हाड़ी लेकर घर में बैठा रहा।

गांव के चौकीदार करिया की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने जेल भिजवाया था। विवेचना में चचेरे भाई उमेश सिंह का नाम पुलिस ने बढ़ाया था। आठ मई 2022 को इस मामले में सिकरीगंज पुलिस ने सोनू व देवेंद्र के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया था।

इस मामले में उमेश को जमानत मिल गई थी। जेल में निरुद्ध सोनू की सोमवार को पेशी थी। न्यायालय में पेश होने के बाद लौटते समय वह सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। जिला कारागार में सोनू बैरक नंबर 22 में निरुद्ध था।

कचहरी में लॉकअप तक नहीं जा पा रहे बंदी वाहनः बताया जा रहा है कि निर्माण होने की वजह से कचहरी में लॉकअप तक बंदी वाहन नहीं जा पा रहे हैं। वाहन बाहर ही खड़ा किया जाता है। पेशी के बाद जब सिपाही बंदी को लेकर बाहर निकल रहा था, इसी दौरान वह चकमा देकर फरार हो गया।

एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि कचहरी लॉकअप के पास से एक बंदी चकमा देकर फरार हो गया है। वह हत्या के आरोप में बंद था। उसकी तलाश चल रही है। बहुत जल्द पुलिस उसे पकड़ लेगी।

एक सप्ताह बाद भी नहीं बनी डिजिटल अटेंडेंस से संबंधित कमेटी, 29 को घेराव की तैयारी तेज

लखनऊ , एजेंसी। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस स्थगित कर दी गई है। बीते मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ हुई वार्ता में तय हुआ था कि इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन एक सप्ताह बाद भी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। इससे शिक्षक परेशान हैं। शिक्षक संगठन फिर से 29 जुलाई को प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में आठ जुलाई से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस का निर्देश जारी किया था। शिक्षकों के भारी विरोध व सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद मुख्य सचिव ने पिछले मंगलवार को शिक्षक संगठनों के साथ बैठक की थी। इसमें डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने व शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई थी।

इसके अगले दिन महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक में भी कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इस बैठक का कार्यवृत्त नहीं जारी किया गया है। विभागीय अधिकारी इस पर कुछ बताने को भी तैयार नहीं हैं। इससे शिक्षकों का इंतजार लंबा होता जा रहा है।

एस-फोर की बैठक 26 कोः परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर चल रहे विरोध व अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (एफ-फोर) की बैठक 26 जुलाई को बुलाई गई है। संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के निर्देश पर राजधानी में होने वाली बैठक में आगे के आंदोलन पर निर्णय होगा।

छठवीं में पढ़ाया जाएगा विष्णु पुराण और कश्मीर का हाल, पाठ्यक्रम में बदलाव

तीन की जगह मात्र एक किताब

वाराणसी , एजेंसी। सीबीएसई में कक्षा छह के विद्यार्थियों को अब महाभारत से जुड़ी बातें, भारत को कैसे मिला नाम, विष्णु पुराण की बातें, पहले और आज की कश्मीर की स्थिति के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही बंगाल के हिस्से, आज के असम और कच्छ के बारे में जानकारी दी जाएगी।

पहले जहां कक्षा छह के विद्यार्थियों को सोशल साइंस की तीन अलग-अलग किताबें पढ़नी पड़ती थीं, अब इसे एक बना दिया गया है। साथ ही पाठों को भी छोटा कर दिया गया है, ताकि पढ़ने में विद्यार्थियों को ज्यादा समय न लगे और सिलेबस समय से पूरा हो सके। नए पाठ्यक्रम में समय को देखते हुए कई बदलाव किए गए हैं।

सीबीएसई की कोऑर्डिनेटर गुरमीत कौर ने बताया कि सोशल साइंस का पाठ्यक्रम पहले काफी लंबा था और विद्यार्थियों को पढ़ने में परेशानी होती थी। साथ ही उन्हें भारत के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब पांच विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम किया गया है। पहला पाठ्यक्रम भूगोल का है, इसमें दो अध्याय शामिल हैं। ये पाठ्यक्रम महासागर और महाद्वीप अथर्ववेद के एक उदाहरण से शुरू होता है, साथ ही हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं जैसे पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाएंगे। आज के विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में बताना जरूरी है। विद्यार्थियों को इन सबकी जानकारी नहीं है। गुरमीत कौर ने बताया कि भारतीय सभ्यता के शुरुआती पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को बाबरी मस्जिद के बारे में जानकारी दी जाएगी।

परिवार पर धारदार हथियार से हमला, बच्ची की मौत और छह घायल

आरोपी गिरफ्तार , जांच में जुटी पुलिस

कानपुर , एजेंसी। कानपुर देहात में भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पिपरी गांव में एक युवक ने घर में सो रहे अपने परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में छह साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि पत्नी, भाई समेत छह गंभीर रूप से घायल हो गए। एसपी ने मौके पर पहुंच घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आरोपी हमलावार को औरैया से पकड़ा गया है। पिपरी निवासी सुंदर प्रताप सिंह की शादी मंगलपुर थाना क्षेत्र के कंचौसी मुनियापुर निवासी पूजा के साथ हुई थी। सुंदर प्रताप की मौत के बाद पूजा ने औरैया के मुरलीपुर निवासी दीपू से शादी कर ली। पूजा पहले पति के दो बेटे आयुष और सूर्यांश के साथ गांव में ही रह रही है। बगल में देवर महेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहता है। रात दो बजे दीपू ने पहले पत्नी पूजा, आयुष व सूर्यांश पर बांका से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद वह महेंद्र के घर में उतर गया। जहां सोते समय महेंद्र उसकी पत्नी बीना, बेटा उमंग व छह वर्षीय बेटी काव्या को घायल कर दिया। काव्या की मौके पर मौत हो गई। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस की बृजेश कुमारी के शोर मचाने पर गांव के लोग दौड़ पड़े। इससे आरोपी दीपू भाग निकला। सूचना पर डायल 112 नंबर पुलिस पहुंची।

ग्रीनपार्क की ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी दर्शक क्षमता ही कतर डाली

कानपुर , एजेंसी। बात 1982 की है। ग्रीनपार्क का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मौका इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का था। तभी इंग्लैंड के बॉब विलिस की एक सनसनाती गेंद को कपिल देव ने बाउंड्री के बाहर भेज दिया। उनका शतक पूरा हुआ और स्टेडियम 44 हजार दर्शकों के शोर से गूंज उठा। मगर, अब वैसा शोर और झूमते दर्शक गुजरे जमाने की बात हो गए।

वजह दर्शक क्षमता का घटते-घटते आधे से भी कम रह जाना है। कुछ आकर्षण बढ़ाने वाले कामों के नाम पर स्टेडियम की बार-बार ऐसी सर्जरी की गई कि दर्शक क्षमता को ही कतर कर फेंक दिया। ग्रीनपार्क की दर्शक क्षमता पर मीडिया सेंटर बनाने के लिए पहली बार 1984 में कैंची चली और फिर कभी वीवीआईपी गैलरी तो कभी डायरेक्टर पवेलियन के लिए इसकी बलि ली जाती रही।

हालत यह है कि 1945 में बने 44 हजार क्षमता वाले इस ऐतिहासिक स्टेडियम की क्षमता अब 15200 ही रह गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर में होने जा रहे टेस्ट मैच से पहले कराए गए आकलन में यही आंकड़ा सामने आया है। वैसे रविवार को टेस्ट मैच की तैयारी का जायजा लेने आए प्रमुख सचिव खेल को अफसरों ने 22230 की दर्शक क्षमता बताई है।

सबसे बड़ी वजह थी, इसमें बनी स्टूडेंट गैलरीः मगर, एक सच यह भी है कि दर्शक क्षमता को लेकर तमाम विभागों के आंकड़े अलग-अलग हैं। गंगा किनारे बने ग्रीनपार्क स्टेडियम की कई वजहों से दुनियाभर में पहचान थी। सबसे बड़ी वजह थी, इसमें बनी स्टूडेंट गैलरी। स्टूडेंट गैलरी वाला दुनिया का यह अकेला क्रिकेट स्टेडियम था। क्षमता भी भारी भरकम 10,000 की थी।

अब अंतरराष्ट्रीय मैच ही नहीं मिलते हैंः इसी की 8000 दर्शक क्षमता का खात्मा कर डायरेक्टर पवेलियन, वीवीआईपी गैलरी और विजिटर गैलरी बन चुकी है। स्टूडेंट गैलरी अब इतिहास की बात है। इसकी दूसरी बड़ी पहचान यहां का मैनुअल लेकिन दुनिया का सर्वोत्तम माना जाने वाला स्कोरबोर्ड था, जिसने इलेक्ट्रॉनिक युग में दम तोड़ दिया। खैर, मुद्दा दर्शक क्षमता है, जिसके लगातार घटने से अब यहां टी-20 और एक दिनी अंतरराष्ट्रीय मैच ही नहीं मिलते हैं।

ग्रीनपार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी यूपीसीए की हैः देश के पांच हेरिटेज क्रिकेट सेंटर में शामिल होने के कारण टेस्ट मैचों की मेजबानी जरूर मिल जाती है। प्रदेश सरकार के पास हुए एमओयू के अनुसार ग्रीनपार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की है, लेकिन यूपीसीए केवल कोई बड़ा मुकाबला होने पर ही आगे आता है। बाकी समय ग्रीनपार्क बेहाल ही रहता है।

इन सुविधाओं के नाम पर घटती रही दर्शक क्षमता

1984 : मीडिया सेंटर के लिए घटा दी 4000 सीटें : 1982 में भारत-इंग्लैंड टेस्ट के दौरान मीडिया सेंटर की मांग उठी तो 1984 में एक गैलरी को तोड़कर मीडिया सेंटर बना दिया गया। इससे दर्शक क्षमता 44 हजार से घटकर 40 हजार रह गई।

2013 : टूट गई स्टूडेंट गैलरी, घटी 8000 क्षमता : क्रिकेट स्टेडियमों में दुनिया की अकेली स्टूडेंट गैलरी को तोड़कर 2013 में डायरेक्टर पवेलियन, वीवीआईपी पवेलियन व विजिटर गैलरी बना दी गई। दर्शक क्षमता 32 हजार रह गई।

2017 : न्यू प्लेयर्स पवेलियन के लिए घटीं 6500 सीटें : डायरेक्टर पवेलियन में नया ड्रेसिंग रूम होने के बावजूद यूपीसीए ने अपनी गैलरी सहित कुछ और गैलरियों को तोड़कर न्यू प्लेयर्स पवेलियन बनाई। क्षमता घटकर 25711 रह गई।

2021 : सीमेंटेड बेंच पर रोक से घटी 2500 क्षमता : सीमेंटेड बेंच जर्जर होने पर 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए टेस्ट मैच में इनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इस मैच करीब 23 हजार दर्शकों को ही प्रवेश दिया गया।

अर्थव्यवस्था को तीव्र गति एवं महाशक्ति बनाने वाला बजट

ललित गर्ग

अक्सर बजट में राजनीति, वोटनीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि-वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते है लेकिन बावजूद यह बजट राजनीति प्रेरित नहीं, देश प्रेरित है। इस बजट में जो नयी दिशाएं उद्घाटित हुई है और संतुलित विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था का जो संकेत दिया गया है, सरकार को इन क्षेत्रों में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहनत करनी होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम सम्पूर्ण बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, उनकी ओर से प्रस्तुत यह बजट एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये आगे की राह दिखाने वाला है। संभावना है कि इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, नौकरीपेशा का थोड़ी राहत, बुनियादी ढांचे में निवेश, पर्यटन को बढ़ावा, आदिवासी उन्नयन, क्षमता विस्तार, हरित एवं कृषि विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी के नये भारत-सशक्त भारत-विकसित पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने सरकार की 9 प्राथमिकताओं -खेती में उत्पादकता और मजबूती बढ़ाना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, मानव संसाधन का समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, अर्बन डेलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्नोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स का ऐलान किया है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति देगा। बजट में जहां बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है वहीं महंगाई को नियंत्रित करने की मंशा साफ दिखाई दी है। विकास, स्टार्टअप और रोजगार सृजन के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा। सातवीं बार बजट प्रस्तुत कर वित्तमंत्री सीमारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।

सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो इस बजट से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इस बजट में मध्यम वर्ग को लम्बे अन्तराल के बाद 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में भी कुछ अहम बदलाव करने का एलान किया है। मौजूदा नियमों के तहत एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ह्यनवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की घोषणा की। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा। मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे पहुंचाने का लक्ष्य है। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से यह बजट कारगर साबित होगा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, रोजगार के नये अवसर सामने आयेंगे, उत्पाद एवं विकास को तीव्र गति मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद इस बजट प्रावधानों के माध्यम से देश को स्थिरता की तरफ ले जाते दिखाई पड़ रहे हैं। बजट हर वर्ष आता है। अनेक विचारधाराओं वाले वित्तमंत्रियों ने विगत में कई बजट प्रस्तुत किए। पर हर बजट लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर ही जाता रहा है। लेकिन इस बार बजट ने अर्थव्यवस्था में नयी परम्परा के साथ राहत की सांसें दी है तो नया भारत- सशक्त भारत-विकसित के निर्माण का संकल्प भी व्यक्त किया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रेलों का विकास, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ किसानों, आदिवासियों, गांवों और गरीबों को ज्यादा तवज्जो दी गयी है। सच्चाई यही है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। इस बार के बजट से हर किसी ने काफी उम्मीदें लगा रखी थीं और उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। विशेषतः नौकरीपेशा लोगों ने राहत की सांस ली है।

संभवतः इस बजट को नया भारत निर्मित करने की दिशा में लोक-कल्याणकारी बजट कह सकते हैं। यह बजट वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशाओं को भी उद्घाटित करता है। आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है बल्कि यह देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण एवं दूरगामी सोच से जुड़ा कदम है। बजट के सभी प्रावधानों एवं प्रस्तावों में जहां ह्यहर हाथ को कामह्न का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं ह्यसबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासह्न का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत यह बजट निश्चित ही अमृत बजट है। जिसमें भारत के आगामी 25 वर्षों के समग्र एवं बहुमुखी विकास को ध्यान में रखा गया है। बीते कुछ सालों में नरेन्द्र मोदी ने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।

आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। बजट में टूरिज्म पर विशेष बल दिया गया है। पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है।. भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। सरकार ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगी, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आशा के अनुरूप ही बजट का फोकस किसानों, आदिवासियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, रोजगार, युवाओं की अपेक्षाओं, विकास और ग्रामीण क्षेत्र एवं पर्यटन पर रखा है। अपने ढांचे में यह पूरे देश का बजट है, एक आदर्श बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। अक्सर बजट में राजनीति, वोटनीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि-वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते है लेकिन बावजूद यह बजट राजनीति प्रेरित नहीं, देश प्रेरित है। इस बजट में जो नयी दिशाएं उद्घाटित हुई है और संतुलित विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था का जो संकेत दिया गया है, सरकार को इन क्षेत्रों में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहनत करनी होगी।

संपादकीय

केदारनाथ में हादसा

ऊत्तराखंड़ स्थित केदारनाथ में गौरीकुंड के पास पहाड़ी से पत्थर नीचे गिरने के कारण तीन लोगों की मौत वाकई दुखद है। हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। दरअसल, पहाड़ों में बारिशों के कारण अक्सर ही जमीन खिसकने (लैंड स्लाइड) के मामले होते रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि लैंड स्लाइड होने के कारण ही यह हादसा हुआ है। हादसा रविवार सुबह हुआ। पहाड़ से बड़े-बड़े. पत्थर गिरने की घटना तीन स्थानों पर हुई। गौर करने वाली बात यह है कि गौरीकुंड़-जहां हादसा हुआ है-वहां से केदारनदाथ धाम तक 16 किलोमीटर लंबे पैदल यात्रा मार्ग पर कई संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां हल्की बारिश में ही पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने लगता है। यह पूरा स्ट्रेच भूस्खलन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है। इस मामले में कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन भारी बारिश हो रही थी और श्रद्धालु यात्रा पर थे। उन्हें इस आशंका का भान ही न हो सका। यहां प्रशासन की जिम्मेदारी को परखना जरूरी बन जाता है। जब यह बात वहां के प्रशासन और आपदा प्रबंधन को मालूम था तो फिर यात्रियों को इसकी जानकारी देना उनका फर्ज था। वैसे भी केदारनाथ में इससे पहले कई हादसे हुए हैं। बीते आठ वर्षों में वषार्काल के दौरान इस मार्ग पर हादसे में 19 व्यक्तियों को जान गंवानी पड़ी। इस नाते वहां के प्रशासन को इसकी तैयारियां चौकस रखनी चाहिए थी। यह घनघोर लापरवाही का मामला है। इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि अब प्रशासन अपनी साख बचाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, मगर यह सब कवायद यात्रा शुरू होने से पहले होनी चाहिए थी। ताजा निर्देश के मुताबिक शाम 5 बजे से दूसरे दिन सूर्योदय तक केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यात्रियों की भी जिम्मदारी है कि वो खुद से खतरा मोल न लें। अगर मौसम साफ है और यात्रा में कोई व्यवधान की अग्रिम सूचना नहीं है तभी आगे बढ़ा जा सकता है। प्रकृति से लड़कर कोई आज तक जीत नहीं सका है। सभी लोगों को उसके रौद्र रूप की वजहों की तलाश करनी होगी और उसका सम्मान भी करना होगा। पहाड़ी राज्यों में लोगों की जरूरत से ज्यादा आवाजाही और अंधाधुंध निर्माण के कार्यों पर बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ना होगा। प्रकृति के साथ तारतम्य बनाने और उसके अनुरूप चलने से ही जान-माल के नुकसान से बचा जा सकता है। यह बात हर किसी को अपने जेहर में रखनी होगी।

चिंतन-मनन

उपाय भी ठीक से हो

एक सास ने बहू से कहा, बहूरानी! मैं अभी बाहर जा रही हूं। एक बात का ध्यान रहे, घर में अंधेरा न घुसने पाए। बहू बहुत भोली थी। सास चली गई, सांझ होने को आई। उसने सोचा कि अंधेरा कहीं घुस न जाए, सारे दरवाजे बंद कर दिए। सब खिड़कियां बंद कर दीं। दरवाजे के पास लाठी लेकर बैठ गई। सोचा- दरवाजा खुला नहीं है, कोई खिड़की खुली है, कहीं भी कोई छेद नहीं। आएगा तो दरवाजा खटखटाएगा, लाठी लिए बैठी हूं, देखती हूं कैसे अन्दर आएगा। पूरी व्यवस्था कर दी। अंधेरा गहराने लगा। सोचा, कहां से आ गया! कहीं भी तो कोई रास्ता नहीं है। हो न हो दरवाजे से ही आ रहा है। अन्धकार को पीटना शुरू कर दिया। काफी पीटा कि निकल जाओ मेरे घर से! मेरी सास की मनाही है कि तुम्हें भीतर घुसना नहीं है! खूब लाठियां बजाई। लाठी टूटने लगी। हाथ छिल गए। लहूलुहान हो गए। अंधेरा तो नहीं गया। परेशान हो गई।

सास आई। दरवाजा खोला। कहा, यह क्या किया? मैंने कहा था कि अंधेरे को मत आने देना घर में। वह बोली, देखो, मेरे हाथ देख लो। लहूलुहान हो गए। लाठी टूट गई। मैंने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर इतना जिद्दी है कि माना ही नहीं और यह तो घुस ही गया। सास ने सिर पर हाथ रखा। कहा, बहूरानी! अंधेरे को ऐसे मिटाया जाता है? क्या अंधेरा ऐसे मिटता है? समझी नहीं तुम बात को। सास ने दीया जलाया, अंधेरा समाप्त हो गया। उपाय के बारे में हमारी जानकारी सही नहीं होती तो हम प्रयत्न तो करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर अंधेरा मिटता नहीं।

...और अब नाम-पहचान पर धर्मयुद्ध?

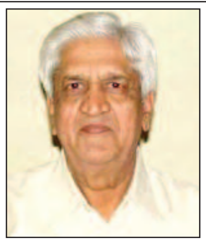
ओमप्रकाश मेहता

आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि समूचा विश्व एक दमघोटू माहौल में जीनें को मजबूर है, साम्प्रदायिकता का यह जहरीला धुंआ हर किसी के दिल-दिमाग में घुटन पैदा कर रहा है, भारत का 'हिन्दूराष्ट्र' का नारा अब विश्वमंच से लगाया जाने लगा है, इस कारण से एक सम्प्रदाय विशेष में डर तथा चिंता व्याप्त हो गई है, अब यह माहौल क्यों बनाया गया और इसके पीछे कौन सी शक्तियां है? इसका उत्तर तो बाद में खोज लिया जाएगा, किंतु प्राथमिकता इस माहौल को खत्म करने की है, क्योंकि यह माहौल यदि खतरे की सीढ़ी पार कर गया तो पूरे विश्व की शांति खतरे में पड़ सकती है। भारत में इस माहौल की शुरूआत देश को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने वाले उत्तरप्रदेश से हुई है, जहां सबसे पहले धार्मिक रैलियों के मार्ग की दुकानों के बाहर उनके मालिकों के नाम की पट्टियां लगाने के आदेश प्रदान किए गए, जिसका सबसे पहले अनुसरण पड़ौसी राज्य उत्तराखण्ड़ ने किया जहां कांवड मार्ग की दुकानों पर इस विवादित नियम को लेकर सख्ती बरती गई। उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड के बाद अब छूत का यह रोग मध्यप्रदेश में भी प्रवेश कर गया है और मध्यप्रदेश स्थित देश की सबसे पूण्य व पवित्र नगरी अवंतिका (उज्जैन) में इस नियम को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश प्रदान कर दिए गए। अब आज देश की सबसे बड़ी और अहम् चिंता यही है कि आखिर इन आदेशों को पालन करवा कर देश-प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहता है? प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने पद ग्रहण करते ही आज से एक दशक पहले प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के 'पंचशील' सिद्धांतों की तो इतिश्री कर ही दी थी, जिनमें भारत में शांति की पहल की गई थी, अब आज के शासक देश को साम्प्रदायिक भट्टी में झौंक कर अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहते है, यदि मोदी जी को अपने तीसरें कार्यकाल में 'हिन्दूराष्ट्र' का संकल्प पूरा करना ही है तो उसके और भी अन्य रास्ते हो सकते है इसके लिए एक सम्प्रदाय विशेष को लक्ष्य बनाने की क्या जरूरत है?

....और अब तो यह मुहीम भारत तक सीमित न रहकर धीरे-धीरे विश्व स्तरीय स्वरूप ग्रहण करती जा रही है, यही आज की चिंता का सबसे बड़ा कारण है यदि देश-विदेश में यही माहौल बना रहा तो इसके परिणाम कितने खतरनाक होगें? इसकी किसी ने कल्पना भी की है? हमारा इतिहास ऐसी मुहीम के परिणामों का गवाह है, इससे आज शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। हमारा पुरातन काल से नारा 'सर्वधर्म समभाव' रहा है, हम आखिर उसे त्यागने को क्यों आतुर है?

शायद इसका मुख्य कारण आज का बदला हुआ माहौल है, हमारा देश हमेशा से धर्मपरायण रहा है, इसीलिए ऋषि-मुनियों ने अपना दबदबा कायम रखा, किंतु अब माहौल एकदम उलट गया है, आज देश के कर्णधार राजनेता साधु-महात्माओं की शरण में नही बल्कि साधु- महात्मा राजनेता की शरण में नजर आ रहे है, अब ऐसे में सहज ही देश, प्रजा और यहां के आध्यात्म के भविष्य की कल्पना की जा सकती है।

वैसे इस स्थिति के लिए कोई दोषी नही है, न राजनेता और न उनके आराध्य। दोषी है तो कुर्सी का मोह, जिसने एक बार कुर्सी प्राप्त कर ली वह उसे 'दीर्घजीवी' बनाने की कौशिश करता है और यही भावना आज की राजनीति का मुख्य केन्द्र है, अब ऐसे में यह सवाल पैदा होना स्वाभाविक है कि इसका ईलाज क्या है? तो सत्य बात यह है कि इसका ईलाज किसी संत-मौलवी या डॉक्टर के पास नही बल्कि स्वयं

रोगी के पास है, जो अपने में आत्म चेतन पैदा कर अपने आपको ठीक कर सकता है और वही अब करना भी चाहिए, दुकानों पर नाम पट्टी लगाने से कुछ नही होगा।

पाकिस्तानः पूर्व सैनिक बनाए जा रहे आतंकवादी

प्रमोद भार्गव

पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर में आतंकवादी हमले तेज कर दिए हैं। धारा 370 के खात्मे के बाद घाटी के हालात में जबरदस्त सुधार देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। स्थानीय स्तर पर घाटी के मुस्लिम युवाओं ने आतंक की राह छोड़कर जब करियर बनाने की दिशा में पहल कर दी तो पाक की भारतीय सीमा में युवाओं को लालच देकर आतंकी बनाने की मंशा पर विराम लग गया।

अतएव अब उसने अपने ही पूर्व सैनिकों को प्रलोभन देकर आतंकी बनाकर घुसपैठ करानी शुरू कर दी। नतीजतन भारतीय जमीन पर एक बार फिर से आतंकी घटनाओं का सिलसिला तेज हो गया। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक सेना के कप्तान समेत पांच जवान शहीद हो गए। सुरक्षाबल निरंतर आतंकियों को मार गिरा रहा है। बावजूद घुसपैठ का सिलसिला बना हुआ है, जो देश और सेना के लिए चिंता का सबब है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक घाटी में करीब डेढ़ माह से जारी आतंकी हमलों में पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिकों की लिप्ता के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। एजेंसियां इसका यह भी मानकर चल रही हैं कि घाटी में भारी मतदान के बाद पाकिस्तान हताशा के दौर से गुजर रहा है। उसे आशंका है कि कहीं विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर प्रांत में लोकतंत्र की बहाली न हो जाए?

इसलिए वह घाटी में हमलों के जरिए माहौल खराब करके दहशत का वातावरण रचने में लगा है। अलगाववादी सुर का आलाप करने वाले मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार को मतदाता ने हराकर यह साबित कर दिया कि घाटी के हालात बदतर करने में इन परिवारों की भूमिका अहम रही है। इससे पाक ने शायद अंदाजा लगाया है कि विधानसभा चुनाव के बाद घाटी में जो प्रजातांत्रिक सरकार बनेगी, वह पाक की मंशा के अनुरूप चलने वाली नहीं है। इसलिए माहौल खराब करके चुनाव को टला जाए। इस बीच पाकिस्तान की फंडिंग से घाटी की तरह जम्मू क्षेत्र में आतंकियों की मदद करने वाले ओवर ग्राउंड कार्यकताओं का एक नेटवर्क भी तैयार किया है। इसे सेना ध्वस्त करने में लगी है। डोडा किश्तवार, पुंछ, राजौरी, रियासी और कठुआ के कठिन भौगोलिक इलाकों में पिछले दो दषक में जैश-ए-मोहम्मद और लश्करे तैयबा ने ओवर ग्राउंड वार्कर नेटवर्क खड़ा किया था। यह अंततरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से आने वाले आतंकियों को घाटी के सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम करता था। घाटी में रहने वाले ये वार्कर घने वनों और दुर्गम इलाकों में छोटे-छोटे घर बनाकर रह रहे हैं। रियासी जिले में हिंदू भक्तों की बस पर गोली चलाने वाले आतंकियों को इन्हीं ओवर ग्राउंड वर्कर ने मदद की थी। भारतीय सेना के अनुसार ओवर ग्राउंड वार्का वे लोग होते हैं, जो उग्रवादी या आतंकवादियों को रसद, नकदी, आश्रय और अन्य रहने लायक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। सेना इस नेटवर्क को नष्ट कर रही है। पाक सेना कितनी दगाबाज है, इसका खुलासा पाक के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एवं पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व अधिकारी शाहिद अजीज ने ह्यद नेशनल डेली' में किया था। इसमें कहा गया था कि कारगिल युद्ध में पाक आतंकवादी नहीं, बल्कि उनकी वर्दी में पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक ही लड़ रहे थे और इस लड़ाई का लक्ष्य सियाचिन पर कब्जा करना था। चूंकि यह लड़ाई बिना किसी योजना और अंतरराष्ट्रीय हालात का अंदाजा लगाए बिना लड़ी गई थी, इसलिए तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने पूरे मामले को रफा-दफा कर दिया था। इससे यह तथ्य तो प्रमाणित होता है कि पाकिस्तानी फौज इस्लामाबाद के पूरे नियंत्रण में नहीं है। आतंकी सरगना हाफिज सईद भारत-पाक सीमा पर खुलेआम घूम रहा है। जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी दहशतगर्दी फैलाने में शरीक हैं।'

पाकिस्तान पूर्व सैनिकों को आतंकी बना रहा है। इसका सत्यापन इस तथ्य से भी होता है कि हाल ही में मारे में जिन आतंकियों से खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं, उनका संचालन आसानी से सेना से प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। इन हथियारों में एम-4 कार्बाइन, 509 टैक्टिगल गन और एम-1911 और स्टेयर एयूजी रायफल बरामद हुई हैं। आतंकियों के पास से अल्ट्रा और माइक्रो रेडियो सेट भी बरामद हुए हैं। इनके नेटवर्क में सेंध लगाना आसान नहीं है। ये उपकरण भी अमेरिका द्वारा निर्मित हैं। अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया था। अतएव ऐसी आशंका है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना द्वारा छोड़े गए हथियार अब जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक पहुंच रहे हैं। यदि यह तथ्य एक ठोस सच्चाई है तो कश्मीर में आतंकी हिंसा का दुश्चक्र बढ़ता दिखाई दे सकता है? दरअसल, ये हथियार पाकिस्तान के जरिए भी आतंकियों को मिल सकते है और सीधे अफगानिस्तान से भी लाए जा सकते हैं। भारतीय एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं, कि इन्हें तालिबान सीधे आतंकियों को आर्थिक बदहाली दूर करने के लिए बेच भी रहा है। पिछले चार वर्ष से आतंकियों के पास स्टेयर एयूजी रायफल होने के सूचनाएं मिल रही थीं।

स्वामी दुर्गम खबर ग्रुप के लिए मुद्रक प्रकाशक ज्योति शर्मा द्वारा मुद्दा हाउस सी ब्लॉक बरात घर के सामने चौरा रघुनाथपुर सेक्टर 22 नोएडा गौतम बुध नगर से मुद्रित एवं ए-28 द्वितीय तल कालिंदी कॉलोनी नई दिल्ली से प्रकाशित संपादक राहुल गुप्ता RNI-No. DELHIN/2008/2623 E MAIL : advtdurgamkhabar@gmail.com, Mob no. +919991351706, 7011031751 किसी भी विवाद की स्थिति में पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदाई

एकाग्रता से बढ़ाएं कार्यकुशलता

काम करते वक्त ध्यान का भटकना लगभग सभी के साथ होता है, किंतु अगर यह बहुत ज्यादा होने लगे तो इससे कार्य पर तो असर पड़ता ही है, व्यक्ति का स्वभाव भी प्रभावित होने लगता है।

जिनमें एकाग्रता की कमी होती है वे बहुत चिंतित, उदास, चिड़चिड़े और सहमे से रहते हैं। कुछ अपराध भावना व हीनभावना के शिकार भी हो जाते हैं। आत्मविश्वास की कमी, असुरक्षा की भावना, कुंठा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन व घबराहट बढ़ जाती है। ध्यान भटकने की समस्या में आमतौर पर आत्म नियंत्रण व व्यवहार नियंत्रण का अभाव होता है। ध्यान भटकने से अक्सर गलतियां होने की संभावना रहती है। जिनका ध्यान जल्दी बंट जाता है, उनकी मनोदशा में भी जल्दी-जल्दी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।

एकाग्रता बढ़ाने के लिए निम्न बातों पर गौर फरमाएं –

- एकाग्रता बढ़ाने के लिए मेडीटेशन और योग करें। इससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास होता है।
- एकाग्रता बढ़ाने के लिए किसी केंद्र बिंदु पर जितनी देर हो सके, ध्यान केंद्रित करें। धीरे-धीरे ध्यान केंद्रित करने का समय बढ़ाएं।
- माता-पिता को चाहिए कि शुरू से ही बच्चों को ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा दें।
- अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से और समय पर करें, इससे काम का अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा और किसी तरह की चिंता भी नहीं रहेगी।
- उद्देश्यों में कामयाब न होने पर भी नकारात्मक विचार आने लगते हैं और नकारात्मक विचार मन में हीनभावना लाते हैं अतः ऐसी भावना से बचें।
- सफलता प्राप्त होने पर स्वयं को सकारात्मक सोच से भरें, जिससे काम करने का उत्साह बना रहे।
- बचपन से ही बच्चों की ताकतों और कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करें। जहां तक हो सके घर का माहौल हंसी-खुशी का बनाकर रखें, ताकि बच्चों में नकारात्मक सोच पैदा न हो।
- अपने कार्य को समय-समय पर रिव्यू करते रहें।
- बच्चों की बातों को अनसुना करने की बजाए गौर से सुनें और उन पर ध्यान दें।
- एकाग्रता से काम करने के लिए शांतिपूर्ण माहौल का होना जरूरी है। इसलिए काम करते समय रेडियो या टीवी न चलाएं।
- काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को अनुदेश देते रहें कि आपका ध्यान केवल अपने निर्धारित काम के अलावा और कहीं नहीं जाए।
- यदि काम करते समय ध्यान टीवी देखने या किसी मनोरंजन के साधन की ओर जाए तो पहले उसे पूरा करें, फिर काम करें। इससे ध्यान भटकेगा नहीं और आपको संतुष्टि भी मिलेगी।
- विद्यार्थियों को चाहिए कि पढ़ाई के दौरान बीच-बीच में ब्रेक लें। ब्रेक के समय पढ़ाई की चिंता छोड़कर हल्का-फुल्का कुछ खा-पी लें। घरवालों के साथ बातें और हंसी मजाक करते रहें। ऐसा करने से मूड बदलेगा और फिर से पढ़ाई करने में अधिक ध्यान लगेगा।

ये हैं सफलता के मंत्र

पढ़ाई में टॉपर बनना आपका सपना है तो इस सपने को आप मेहनत से हकीकत में बदल सकते हैं। इन सक्सेस मंत्रों को अपनाकर प्रतियोगी परीक्षा और एक्जाम में सफल हो सकते हैं।

कड़ी मेहनत– सफलता हासिल करने का पहला मंत्र है कड़ी मेहनत। मेहनत का कोई शॉर्टकर्ट नहीं होता। यदि अ प न` पाठ्?यक्रम की आवश्यकता के अनुसार कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका फायदा मिलता ही है।

खुश रहें– किसी भी परीक्षा की तैयारी के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रखें। हमेशा पॉजीटिव थिकिंग रखें। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें।

फोकस बनाए रखें– बिना फोकस बनाकर कई घंटे पढ़ाई करने से अच्छा है कि कुछ घंटे ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। कुछ देर ही सही पर मन को एकाग्र रखकर पढ़ाई करें।

सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करें– हमेशा जीवन में बड़े सपने देखें और लागं टर्म गोल बनाएं। जब भी ऐसा लगे कि आप हार रहे हैं तो अपने सपनों को याद करें। खुद को यह अहसास दिलाएं कि सफने इतने कीमती हैं कि ऐसा संघर्ष उन सपनों के सामने कुछ भी नहीं है।

ऐसे मिलती है सफलता

अक्सर देखा जाता है कि युवा जब अपना सफल करियर नहीं बना पाते हैं तो इसका दोष वे दूसरों को देते हैं। अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने लगते हैं। यह याद रखिए अपनी नाकामी के जिम्मेदार आप खुद हैं।

वे अनेक बातों का रोना रहते हैं, जैसे हमारे माता-पिता के कम पढ़े-लिखे होने के कारण वे हमारा करियर में मागदर्शन नहीं कर सके। हम पढ़ने की सुविधाएं नहीं मिली। पढ़ाई के दौरान हमें घर के कामों में लगाए रखा। घर में ज्यादा सदस्य होने से घरवालों ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया।

ये ऐसी कुछ बातें हैं जो असफल युवा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति कुछ करना चाहे और उसके हौसले बुलंद हों तो उसकी राह में कितनी भी मुसीबतें आएं वह सफल हो जाता है।

एक अंग्रेजी कहावत का हिन्दी अर्थ है– किसी एक विचार या लक्ष्य के प्रति समर्पण के कारण ही एक सामान्य योग्यता रखने वाला व्यक्ति असाधारण प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति बनता है।

कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं बस उनका स्वरूप और उनसे लड़ने के तरीके अलग हो सकते हैं। उन कठिनाइयों को ढाल बनाकर अपनी नाकामी को उजागर न करें, बल्कि हर स्थिति से निकलना सीखें।

याद रखिए दुनिया भी उन्हीं को याद रखती है जो संघर्षों से निकलकर सफलता के शिखर पर पहुंचता है। नाकामियों को रोना छोड़कर चल पड़िए मंजिल की राह पर। मुश्किलें तो आएंगी। अपनी नाकामियों को सफलता की मंजिल पाने का पड़ाव मानिए।

हिटलर का प्रसिद्ध वाक्य है, जो बिना संघर्ष के जीतता है वह विजेता कहलाता है लेकिन जो संघर्षों का सामना करके जीतता है वह इतिहास बनाने वाला कहलाता है।

इन बातों जीवन में हमेशा रखें ध्यान–

- अगर आप किसी क्षेत्र में करियर बनाने में असफल हो गए हैं तो यह न सोचिए कि सिर्फ वही क्षेत्र आपके लिए बना था।
- आप दूसरे क्षेत्र में प्रयास कर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
- पहाड़ी की चढ़ाई करते समय हमेशा ऊपर चढ़ने वालों को देखना चाहिए। नीचे वालों को देखेंगे तो हमें ऊंचाई से डर लगेगा।
- अपने आपको मोटिवेट कीजिए। सफलता की जो अनुभूति रहती है उसका मजा ही कुछ और है।
- जीत कुछ कर गुज़रने में है, हारकर बैठने में नहीं। प्रयास से सफलता मिल ही जाती है।

फोटोग्राफी में रखें इन बातों का ध्यान

फैशन और वाइल्ट लाइफ फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले युवा इसे अपना पेशन मानते हैं। इस फील्ड में क्रिएटीविटी, टेक्निक, ट्रेनिंग, हार्डवर्क, ग्लैमर, एडवेंचर सबकुछ है। सही ट्रेनिंग और गाइडेंस से इस फील्ड में करियर बनाने का स्कोप बढ़ गया है। कई डिग्री होल्डर फोटोग्राफर्स भी फैशन और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बारीकियां सीख रहे हैं।

करियर संभावनाएं– फैशन इंडस्ट्रीज, कार्पोरेट और इंडस्ट्रीयल सेक्टर के विकसित होने से इस फील्ड में संभावनाएं बढ़ गई हैं। फैशन इंडस्ट्री के फलने-फूलने के साथ ही फैशन फोटोग्राफी में ग्लैमर जुड़ चुका है। आज हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ कैलेंडर, मैगजीन, विज्ञापन ब्रोशर प्रकाशित करती है। इनमें आकर्षक और स्टाइलिश फोटो की खास भूमिका होती है। इन सबके लिए फैशन फोटोग्राफर की बहुत जरूरत है। तकनीकी रूप से सक्षम होने पर इस क्षेत्र में भविष्य बहुत उज्जवल है।

शैक्षणिक योग्यता– फोटोग्राफी के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। देशभर में कई इंस्टीट्?यू फोटोग्राफी में डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं। एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनने के लिए डीप स्टडी और अच्छे विजन का होना जरूरी है। अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, औरंगाबाद जैसे शहरों में संस्थानों द्वारा फोटोग्राफी का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है। इन संस्थानों में दो-तीन वर्षों के डिग्री कोर्स एवं ट्रेनिंग दी जाती है।

इन बातों का रखें ध्यान–

- फोटोग्राफर बनने के लिए किताबी कम और प्रेक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी है।
- अपने फील्ड की पूरी जानकारी, लेटेस्ट ट्रेंड पर नजर और आने वाले ट्रेंड की खबर होना जरूरी।
- फोटोग्राफी का बेसिक नॉलेज के लिए किसी प्रतिष्ठित इंस्टीट्?यूट से ट्रेनिंग लें।
- ट्रेनिंग के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है विजन।
- इस फील्ड में बहुत ज्यादा पेशन रखने की जरूरत है। यह फील्ड पेशन, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क मांगता है।
- फोटोग्राफी में सक्सेस धीरे-धीरे ही मिलती है।

फोटोग्राफी के टॉप इंस्टीट्यूट

- नेशनल इंस्टीट्?यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद।
- सर जेजे स्कूल ऑफ एप्लाइड आर्ट, मुंबई।
- जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद।

कैसे सामना करें इंटरव्यू का

इंटरव्यू का नाम आते ही दिल में एक डर पैदा होने लगता है। इंटरव्यू के लिए आपको हर तरह से तैयार रहना पड़ता है। इंटरव्यू से पहले कई अनजाने सवाल सताने लगते हैं।

कहते हैं कि वेल बिग्निंग इज हाफ डन अगर आपने इंटरव्यू में शुरू से ही अपना विश्वास बनाए रखा और इंटरव्यू पेनल के शुरुआती सवालों का प्रभावशाली अंदाज में जवाब दे दिया तो मान लें कि आपकी सफलता की संभावनाएं प्रबल हैं।

इटरव्यू में जाने से पहले नीचे दिए गए टिप्स पर गौर करें। ये टिप्स आपके लिए बड़े मददगार साबित होंगे। टिप्स पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है।

1. कहा जाता है कि पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है। इसलिए मेंटल लेवल पर तैयारी के साथ-साथ आप यह न भूल जाएं कि इंटरव्यू में आपकी बौद्धिक क्षमता के अलावा आपकी बॉडी लेंग्वेज को भी परखा जाएगा। वेल ड्रेस्ड होकर ही इंटरव्यू में जाएं क्योंकि इससे आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे।
2. अपने साथ जरूरी कागजात जरूर ले जाएं। मसलन अपने सर्टिफिकेट, एकेडमिक एचीवमेंट और बायोडाटा जो आपने इंटरव्यू से पहले भेजा था, उसकी एक प्रति अवश्य ले जाएं।
3. अपने कागजात इंटरव्यू में तभी प्रस्तुत करें, जब आप से मांगें जाएं।
4. इंटरव्यू में लेट न हों। कम से कम पंद्रह मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें।
5. यदि किसी कारण न चाहते हुए भी इंटरव्यू में लेट हो जाएं तो उसके लिए सबसे पहले क्षमा मांगें और देर से आने के कारण का उल्लेख करें।
6. इंटरव्यू कक्ष में पहुंचते ही इंटरव्यू पैनल के सदस्यों का अभिवादन जरूर करें।
7. इंटरव्यू पैनल के हर सवाल को ध्यान से सुनें और यदि किसी सवाल को सुनने में कोई शक हो तो निम्रतापूर्वक उसे दोहराने के लिए कहें।
8. सवालों के जवाब विश्वास के साथ और संक्षेप में दें जब तक कि विस्तृत जानकारी देने के लिए न कहा जाए।
9. जिस संस्थान में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में मोटी जानकारी पहले ही जुटा लें।
10. जब आपसे पूछा जाए कि इस पद के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है तो इसका जवाब चतुराई से दें। सीधे ही कोई फिगर बताने से बेहतर होगा कि आप कहें कि एस पर द मार्केट स्टेंडर्ड। इंटरव्यू पैनल के दोबारा पूछने पर आप अपने मुताबिक कोई फिगर बता सकते हैं।
11. इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू पैनल से आई कॉन्टेक्ट कायम रखें।
12. अगर किसी विषय में जानकारी नहीं है तो उसे स्वीकार कर लें।
13. कभी झूठ न बोलें। अगर इंटरव्यू पैनल ने आपका झूठ पकड़ लिया तो आपकी सारी इंप्रेशन खराब हो जाएगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए नई समितियों का गठन

दुर्गम खबर
गौतमबुद्ध नगर, : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) हेतु पर्यावरण प्रबंधन समिति (एईएमसी), हवाई अड्डा आपातकालीन योजना समिति, अपहरण विरोधी आकस्मिक योजना) पर कमेटी गठित करने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एयरपोर्ट एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त कमेटियों के संबंध में पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

आयोजित बैठक में हवाई अड्डे के संचालन में अनुपालन की जाने वाले तीन बिंदुओ, जिसमें हवाई क्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन समिति (एईएमसी), हवाई अड्डा आपातकालीन योजना समिति, अपहरण विरोधी आकस्मिक योजना) पर संक्षेप में चर्चा हुई। सीओओ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किरण जैन द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि यह एनआईए में आपातकालीन और अपहरण प्रतिक्रिया, बाधा हटाने और प्रबंधन के लिए एक सहयोगात्मक और स्पष्ट दिशा स्थापित करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने का पहला कदम है।

जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों के मतों का अनुश्रवण करते हुए उपरोक्त समितियों के गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा उत्सव शर्मा, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ग्रेटर नोएडा डी के गुप्ता, ए आर एम ग्रेटर नोएडा अनिल कुमार शर्मा, किरण जैन सीओओ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुख्य परिचालन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मानवता भलाई के कार्य कर रहे डेरे सच्चा सौदा के अनुयायी

दुर्गम खबर
नोएडा। संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह इन्सां की प्रेरणा में चलते हुए डेरा सच्चा सौदा की साध संगत हमेशा ही मानवता भलाई के कार्यों में अग्रसर रहती है। पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा की साध संगत 163 मानवता भलाई कार्य कर रही है।इसी क्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर भी इसी के तहत 4 मानवता भलाई कार्य किए गए।पहला वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया गया। यह पहल पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।दूसरा मीठे पानी की छबील गर्मियों में लोगों को ठंडक पहुँचाने और उन्हें तरोताजा रखने के लिए मीठे पानी की छबील का आयोजन किया गया।तीसरा गरीब बच्चों को स्टेशनरी देना और उनका स्कूल में प्रवेश कराकर उनकी आर्थिक सहायता करना (स्माइल ऑन इनोसेंट मुहिम के तहत) - शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, साध संगत ने गरीब बच्चों को स्टेशनरी वितरित की और उनका स्कूल में प्रवेश कराया। इसके साथ ही, उनकी आर्थिक सहायता भी की गई ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें।चौथा गरीब बच्चों को कपड़े देना आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को कपड़े प्रदान किए गए ताकि वे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें।इस प्रकार, डेरे सच्चा सौदा की साध संगत ने मानवता की सेवा के अपने संकल्प को जारी रखते हुए, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को मानवता भलाई के कार्यों के माध्यम से मनाया। यह प्रेरणा हमें संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह इन्सां जी से मिलती है, जो हमें सदैव मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते हैं।

सरकार बचाओं महंगाई बढ़ाओ के नारे को पूर्ण करता बजट : राकेश अवाना

दुर्गम खबर-नोएडा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारम द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर जहां सुबह से ही लोग चर्चा- परिचर्चा में व्यस्त रहे, वहीं बजट शुरू होते ही लोग टीवी से चिपक गए। इस दौरान किसी ने बजट की सराहना की, तो किसी ने इसे निराशापूर्ण बताया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पूर्ण बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न कारकों को सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा, कैसे देश में विकास की गति को तेज किया जा सके, इस दिशा में भी बजट के जरिए नई रूपरेखा खींचने का प्रयास किया गया है। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने इसे लोगों के कल्याण से जुड़ा बजट बताया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें लोगों के हितों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।वही कुछ लोगों ने इस बजट को

निराशापूर्ण बताया।इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के गौतमबुद्ध नगर जिलाध्यक्ष राकेश अवाना ने बजट पर अपनी राय देते हुए कहा कि इस बजट ने देश के हर वर्ग को निराश किया है।ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार का बजट "सरकार बचाओं - महंगाई बढ़ाओ" के नारे को पूर्ण कर रहा है।बजट में केंद्र सरकार ने एक या दो नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र नहीं किया है। इसमें मनरेगा का जिक्र नहीं किया गया, जो गरीबों के लिए सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी लाने की दिशा में भी बजट में कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। इस बजट में किसान की MSP दुगुना नही हुयी,कर्मचारी को OPS नही मिला। वही ना जाने नौजवान कब तक अग्निवीर योजना में फंसा रहेगा और कब तक महिलाए यू ही मंहगाई की मार झेलती रहेंगी।

कांवरियों की सेवा में कोई कमी ना छोड़ी जाए : चैनपाल प्रधान

दुर्गम खबर
ग्रेटर नोएडा। सावन के महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही भोले के भक्तों की कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग कावड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं। इस बीच
हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष चैनपाल प्रधान ने कांवड़ियों पर संभावित खतरे को लेकर जिला प्रशासन से अपील की है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाए।आपको बता दे कि हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष चैनपाल प्रधान ने कि सावन मास में चल रहे कावड़ यात्रा पर विशेष ध्यान देते हुए कांवरियों की सेवा में कोई कमी ना छोड़े जाए।उन्होंने कहा कि प्रशासन की सतर्कता बेहद जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है की कावड़ यात्रा में शिव भक्तों के साथ दुर्व्यवहार व कावड़ को खंडित कर

दिया जाता है।उन्होंने जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि ऐसी घटना जिला में ना घटित हो इस पर अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। जिला प्रशासन के अधिकारी समय-समय पर कावड़ यात्रा रूट का निरीक्षण भी करें जिससे जो कमी हो उसे पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा है कि पूरे 1 महीने तक चलने वाले कावड़ यात्रा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो इसकी पूरे जिम्मेदारी जिला प्रशासन के अधिकारियों की होनी चाहिए।

किसान इंटर कॉलेज में हुआ वृक्षारोपण

दुर्गम खबर
दनकौर : क्षेत्र के गांव पारसौल स्थित किसान इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री के आवाहन एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के करीब 200 पौधे रोपे गए।
जिनमें पीपल ,जामुन ,अमरुद ,नीम , पापड़ी आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रोपण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर "एक पेड़ मां के नाम" कार्यक्रम को सार्थक करते हुए कालेज प्रधानाचार्य यशपाल सिंह ने छात्र-छात्राओं को वृक्षारोपण का महत्व बताया एवं सभी छात्र-छात्राओं को उनके द्वारा रोपित किये गए वृक्षों की सुरक्षा के लिए शपथ दिलाई । इस अवसर पर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पारसौल गौतमबुद्धनगर डॉक्टर सुशील कुमार पांडे एवं डॉ दिव्या ने भी 50 पौधों का कॉलेज के लिए सहयोग प्रदान किया । इस अवसर पर कॉलेज का समस्त स्टाफ, कर्मचारीगण एवं सैकड़ो छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की।

युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों और व्यापार का बजट : राजीव शर्मा

दुर्गम खबर-नोएडा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वां केंद्रीय बजट पेश किया।देखा जाए तो इस बजट में इनकम टैक्स देने वालों को राहत दी गए।नई टैक्स रिजीम में अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।विश्लेषकों के मुताबिक 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। जिससे टैक्सपेयर को 17 हजार 500 रुपए का फायदा होगा।बजट में कैंसर की दवा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी-फूडस की कीमतों में कमी लायी गयी है।इसी बजट पर अपनी राय देते हुए आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सेक्टर 62 राजीव शर्मा ने कहा कि बजट 2024-25 में सर्वांगीण, सर्वव्यापी तथा सर्व-समावेशी विकास के साथ वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' की परिकल्पना की गई है। यह बजट युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों

और व्यापार का बजट है, अगर कुल मिलाकर कहें तो यह बजट देश को आगे ले जाने वाला जरूरतमन्दों का बजट है।इस बजट में कृषि, युवा रोजगार, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित किया गया है। उम्मीद की जा सकती है कि जब आजाद भारत 2047 में 100 वर्ष का होगा तो हर तरफ सुनहरा सुनहरा सा होगा यानि भारत पूर्ण विकसित खुशहाल देश होगा। भारत के समृद्ध भविष्य के लिए धरातल पर कार्य करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद व शुभकामनाएं।

अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, छह शातिर चोर गिरफ्तार

दुर्गम खबर-धीरेन्द्र अवाना
नोएडा। नोएडा पुलिस को उस वक्त एक नई सफलता मिली जब थाना सेक्टर -113 पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पदार्फाश करते हुए छह शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है।इनके कब्जे से पुलिस को दस लग्जरी कारें बरामद हुई हैं।वही पकड़े गए चोरों ने वाहन चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है।चोरों की पहचान मुरादाबाद निवासी खलील,सम्भल निवासी मोनू , हरियाणा निवासी सोनू व प्रमोद,पंजाब निवासी राजेश और महाराष्ट्र निवासी अली शेर के रुप में हुयी।आपको बता दे कि पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में अपराधियों पर निरंतर अंकुश लगाया जा रहा है।इसी क्रम में डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा ने अपनी टीम के साथ अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पदार्फाश करते हुए छह शातिर चोरों को गिरफ्तार किया।आपको बता दें कि नोएडा जोन के डीसीपी रामबदन सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सेक्टर-112 स्थित भारत हॉस्पिटल के पास से चोरी के फॉर्च्यूनर कार में जा रहे सोनू, मोनू, खलील, राजेश, प्रमोद, अली शेर को गिरफ्तार किया। इनके निशानदेही पर चोरी की कार, क्रेटा कार, एक ब्रेजा कार, एक स्विफ्ट कार, एक टाटा सूमो, एक इको कार सहित 10 कार बरामद की गई।पकड़े गए आरोपी शातिर वाहन चोर हैं और लग्जरी गाड़ियों को निशाना बनाते हैं। इनके पास से बरामद फॉर्च्यूनर कार कुछ दिन पूर्व थाना क्षेत्र से चोरी की थी।पकड़े गए आरोपियों पर नोएडा दिल्ली गाजियाबाद में वाहन चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं।

एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना में दर्जी के प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यार्थियों का किया जाएगा अभिलेखों का सत्यापन

दुर्गम खबर-गौतमबुद्ध नगर : जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र गौतम बुद्ध नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना में दर्जी के प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in / msme.up.gov.in पर प्राप्त आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन करने लिए अभिलेखों का सत्यापन करने हेतु कार्यालय उपायुक्त, उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र सूरजपुर(कलेक्ट्रेट के निकट/पीछे ईकोटेक 2) ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के परिसर में 24 जुलाई 2024 को प्रातः 11:00 बजे से 04:00 बजे अभ्यर्थी प्रस्तुत हो। अभिलेखों का सत्यापन 90 से 100 स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभिलेखों के सत्यापन के समय उक्त योजना में प्रशिक्षण के लिए भरे गए ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बैंक पासबुक की एक फोटो कॉपी, जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड सही लिखा हो, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (यदि हो), तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र(यदि हो), आय प्रमाण पत्र (यदि हो), जाति प्रमाण पत्र (यदि हो), विशिष्ट श्रेणी (विधवा/तलाकशुदा/सिंगल मदर/दिव्यांग यदि हो) आदि दस्तावेजों के साथ अभ्यर्थी उपस्थित हो।

दादरी-मारीपत रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित फाटक संख्या 148/एसपीएल, 24 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक मरम्मत कार्य के कारण रहेगा बंद

आम नागरिक उक्त अवधि में दादरी स्टेशन के पास आरओबी का कर सकते हैं उपयोग

दुर्गम खबर-गौतमबुद्ध नगर : उत्तर मध्य रेलवे दादरी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने बताया कि दादरी-मारीपत रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित फाटक संख्या 148/एसपीएल पर मरम्मत कार्य होने के फलस्वरुप 24.07.2024 प्रातः 08:00 से 28.07.2024 शाम 06:00 बजे तक बंद रहेगा। इस संबंध में उन्होंने आम नागरिकों को जानकारी दी है कि इस मार्ग से जाने वाले नागरिक सड़क यातायात बंद होने की अवधि के दौरान दादरी स्टेशन के पास आरओबी का उपयोग कर सकते हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मत्स्य पालक एवं मछुआ समुदाय के व्यक्ति विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in पर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

दुर्गम खबर-गौतमबुद्ध नगर : जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में सहायक निदेशक मत्स्य गौतम बुद्ध नगर ने बताया कि वर्ष 2024-25 में मत्स्य विभाग के अंतर्गत मत्स्य पालकों एवं मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु 22 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in पर पुनः मत्स्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पोर्टल पर आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालक एवं मछुआ समुदाय के व्यक्ति योजना की विस्तृत जानकारी के लिए जनपदीय कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य गौतम बुद्ध नगर कमरा नंबर 305, 306 द्वितीय तल विकास भवन जनपद गौतम बुद्ध नगर से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।

जनपद के समस्त दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थी पेंशन बैंक खाते को आधार से एनपीसीआई मॉडल में कराये लिंक

दुर्गम खबर-गौतमबुद्ध नगर : निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने जनपद के समस्त दिव्यांगजन एवं कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन की आगामी किस्त का भुगतान आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। अतः सभी दिव्यांगजन एवं कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थी अपने बैंक से संपर्क कर अपने पेंशन संबंधी बैंक खाते को आधार से एनपीसीआई मॉडल में जल्द से जल्द लिंक कराना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी आगामी पेंशन धनराशि खाते में अंतरित होने में समस्या हो सकती है।

धर्म-कर्म भोले इंसान मृत समान - महाराज जितेंद्र व्यास

दुर्गम खबर-दनकौर : महाराज जितेंद्र व्यास ने बताया कि अपना धर्म-कर्म भूलने वाला इंसान मृत समान होता है कस्बा बिलासपुर स्थित बालाजी मंदिर मे सोमवार को भागवत कथो के चौथे दिन वृंदावन धाम से पधारे जितेंद्र व्यास महाराज ने कंस व देवकी

का वर्णन करते हुए कहा कि जब कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के पश्चात विदा कर रहा था इस दौरान आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा और आकाशवाणी के बाद कंस ने देवकी को रथ से खीच कर मारने का प्रयास किया। देवकी की बहुत विनती के बाद उसे कारागार में डाल दिया और उसके 6 पत्रों की हत्या कर दी उसके बाद कृष्ण का जन्म हुओ और इस प्रशंग के बाद कृष्ण जन्म का उत्सव मंदिर में मनाया गया। व्यासजी महाराज ने कहा कि जो इंसान अपने धर्म - कर्म को भूल जाता है वह इंसान मरे समान होता है इंसान को कभी भी अपने धर्म व कर्म को नहीं भूलना चाहिए सनातनी भाइयों में एकता व सहायता का भाव अत्यंत आवश्यक है भागवत कथा के दौरान बालकृष्ण दास, सुनील पाठक, नवनीत अग्रवाल, सोहनपाल शर्मा, सीताराम तायल, हरि कुमार मित्तल, गिरीश कुमार , लालाराम ,रमन वर्मा`, ओम दत्त कौशिक ,अविनाश कुमार मित्तल ,अश्विनी शर्मा, ममता मैडम आदि भक्तजन उपस्थिते उपस्थित है`।

केंद्र सरकार के बजट में किसानों को मिला धोखा-कृष्ण नागर

दुर्गम खबर-दनकौर : केंद्र सरकार के पैसा की बजट में किसानों को धोखा मिला है किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव कृष्णा नगर में कहा कि केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है जिसमें किसान नौजवान गरीब मजदूरों के लिए कुछ नहीं है किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण नागर ने कहा कि केंद्र सरकार जो बैसाखी से चल रही है और उसको बचाने के लिए सरकार ने आँध्र प्रदेश व बिहार पर फोकस किया है बाकी सभी वर्गों को निराश करने का काम किया है एमसपी एवं स्वामीनाथन रिपोर्ट एवं कर्ज.मुक्ति की बाट जोह रहे किसानों को धोखा मिला है महिला सुरक्षा पर कोई नीति नहीं बनाई है किसानो के बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं बढती महंगाई पर कोई राहत नहीं दी गई यह बजट ऊँट के मुँह में जीरा हैं इस बजट से सभी वर्गों में निराशा है !

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नेमप्लेट हटाने से डर रहे कारोबारी

मुजफ्फरनगर ।उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर होटल से लेकर ठेले वालों के लिए नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था।इसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम आदेश के बावजूद अभी दुकानदार नेमप्लेट हटाने से डर रहे हैं। इसके लिए अभी भी प्रशासन की हरी झंडी का इंतजार हो रहा है।मुजफ्फरनगर के दुकानदार ने बताया कि वे अभी नेमप्लेट हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण की तरफ से निर्देश का इंतजार कर रहे हैं।वहीं एक अन्य दुकानदार ने कहा कि दस दिन पहले तक हर रोज का खर्च 15 हजार रुपये था।लेकिन पिछले 24 घंटे में केवल 4 हजार की कमाई हुई है।हालांकि चाय और खाने में पूरी सतर्कता बरतते हैं, लेकिन लोग नाम पढ़कर ही आगे बढ़ जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये बोर्ड परमानेंट के लिए हटने चाहिए। इससे दुकानदारी घट गई थी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है।हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है।हां जी हमने बोर्ड हटा दिए हैं, देखिए यह भेदभाव था यह बोर्ड परमानेंट हटने चाहिए।इससे कारोबार पर बहुत गलत असर पड़ रहा था, जिससे दुकानदारी घट गई थी।

चेन्नई एयरपोर्ट पर .... जब मधुमक्खियों ने फ्लाइट को घेरा

रायपुर ।चेन्नई एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब घटना हुई, यहां रायपुर जा रही एक फ्लाइट पर मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया।हजारों मधुमक्खियों ने प्लेन को घेर लिया, इससे उड़ान में दो घंटे की देरी हुई। फ्लाइट में छत्तीसगढ़ भाजपा नेता मितुल कोठारी सहित 150 यात्री सवार थे।मधुमक्खियों की संख्या इतनी थी कि यात्री डर से फ्लाइट में सवार होने के लिए बस से उतर नहीं सके।घटना तब हुई जब यात्रियों को बस से प्लेन तक ले जाया जा रहा था।तभी अचानक, बड़ी संख्या में मधुमक्खियां दिखाई दीं और उन्होंने पूरे प्लेन को घेर लिया। ग्राउंड स्टाफ ने खुद को प्लास्टिक के कवर से ढककर मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियां प्लेन के इंजन के पास जमा होने लगीं। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ को केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। धीरे-धीरे मधुमक्खियों की संख्या कम हुई और यात्रियों को सुरक्षित रूप से प्लेन में चढ़ाया गया। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंजन में कोई मधुमक्खी न फंसी हो, फ्लाइट इंजीनियर्स ने प्लेन की पूरी जांच की। इसके बाद ही प्लेन को उड़ान भरने की अनुमति मिली। इस घटना के बारे में भाजपा नेता कोठारी ने कहा कि जब हम बोर्डिंग के लिए बस में सवार हुए, तभी हमें बड़ी संख्या में मधुमक्खियां दिखाई दीं। उन्होंने कहा कि ग्राउंड स्टाफ ने प्लास्टिक के कवर से खुद को ढक लिया और मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश की।उन्होंने कहा कि मधुमक्खियां प्लेन के इंजन के पास जमा हो गई थीं, जिसके बाद स्टाफ ने केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करके उन्हें हटाया।

बीआरएस नेता कविता 26 जुलाई को कोर्ट में होंगी पेश, राउज़ एवेन्यू ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मामले में बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कविता को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। बता दें सीबीआई ने इस साल जून में आरोप पत्र दाखिल किया था और दावा किया था कि मामले में उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सारे सबूत मौजूद हैं।सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी।कोर्ट ने सीबीआई मामले में आरोपी कविता और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले, ईडी ने भी बीआरएस नेता कविता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने दावा किया था कि कविता ने तथाकथित साउथ ग्रुप के सदस्यों और आप नेताओं के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुचित लाभ लेने की साजिश रची थी। दिल्ली की शराब नीति को अब खत्म कर दिया गया है।जांच एजेंसी ने दावा किया कि कविता ने साजिश और इंडो स्पिरिट्स के गठन के जरिए 292.8 करोड़ रुपए की अपराध आय के सृजन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया, जो साजिश और रिश्वत के भुगतान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई थी।बता दें कि के. कविता को लेकर ईडी का दावा था कि आप नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी।कविता, इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थीं. इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी हैं।ईडी के मुताबिक के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी।कविता को ईडी ने इस साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।

भारी बारिश... एन-1 बी डेम क्षतिग्रस्त

दंतेवाड़ा ।छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम मेहरबान राज्य के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है।बस्तर इलाके में भीषण बारिश से आसपास के जिलों में बाढ़ के हालात बने हैं।दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल पहाड़ी में एनएमडीसी द्वारा निर्मित एन-1 बी डेम क्षतिग्रस्त हुआ है।जिला प्रशासन ने बताया कि अत्याधिक बारिश के कारण डेम क्षतिग्रस्त हुआ है।इसकारण अनेक घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा किरंदुल के गाटर पुलिया एवं सीएससी सेंटर के पास भी बारिश से जल जमाव हो गया है।इसके साथ ही जिला प्रशासन मौके पर तैनात होकर रेस्क्यू कर रहा है तथा प्रभावित परिवारों को मंगल भवन में ठहराया जा रहा है। वर्तमान में उनकी स्थिति सामान्य है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के समीप रहने वाले लोगों को अन्य जगह शिफ्ट होने की हिदायत दी जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।नया मानसूनी सिस्टम पूरे प्रदेश में सक्रिय है जिस कारण से तेज बारिश हो रही है।राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून से अब तक राज्य में 355.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी के घर तक लेटकर क्यों पहुंचा सरपंच

महासमुंद (ईएमएस)।छत्तीसगढ़ के एक सरपंच ने दिल्ली में अनोखा प्रदर्शन किया है।केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास मांग लेकर एक सरपंच सड़क पर लेटते हुए उनके आवास तक पहुंचा।सरपंच की मांग है कि उसके गांव में सड़क नहीं है।इसलिए वे गांव में सड़क निर्माण के लिए केन्द्रीय मंत्री के पास पहुंचा है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ग्राम पंचायत बंबूरडीह के सरपंच शत्रुघ्न चेलक हैं।सरपंच अपने गांव में सड़क निर्माण के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं बन रही है।बताया जाता है कि गांव के लोगों ने चंदा करके सरपंच को पांच हजार रुपये दिए। सरपंच इन पैसों से दिल्ली पहुंचा और सड़क की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया।हालांकि सरपंच से गडकरी की मुलाकात नहीं हुई।जानकारी के अनुसार, गड़करी उस समय अपने आवास पर नहीं थे।सरपंच चेलक ने बताया कि वह दो किमी की सड़क बनवाने के लिए नेता और अधिकारियों की चक्कर लगाते-लगाते थक चुके हैं।कहीं से भी उन्हें सड़क बनाने का भरोसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह सड़क रामाडबरी से बावनकेरा गांव तक बननी है।अभी कच्ची सड़क है।बारिश के सीजन में सड़क पर चलना मुश्किल होता है।सरपंच ने बताया कि गांव में सड़क नहीं होने से लोग गांव में शादी करने नहीं आते हैं।लड़के-लड़कियों की शादी सड़क के कारण नहीं हो पाती है।ग्रामीण भी लगातार इस सड़क के लिए मंत्री और नेताओं से मिलते हैं लेकिन अभी तक सड़क बनाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ।सरपंच ने बताया कि इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमारे गांव का नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में ही नहीं है।

नौसेना प्रमुख ने दी रक्षा मंत्री को युद्धपोत में हुए नुकसान की जानकारी

नई दिल्ली। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नौसेना के युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने से हुए नुकसान की जानकारी दी है।आईएनएस ब्रह्मपुत्र में सोमवार को आग लग गई थी।इस हादसे में युद्धपोत को काफी नुकसान हुआ है। नौसेना के मुताबिक बाद में यह युद्धपोत एक तरफ झुक गया और कोशिशों के बावजूद इसे सीधा नहीं किया जा सका। एडमिरल त्रिपाठी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को सोमवार शाम को ही इस हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी।नौसेना प्रमुख स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को मुंबई पहुंचे।

बिना मुस्लिमों के नहीं हो सकती अमरनाथ-वैष्णो देवी यात्रा, कांवड़ यात्रा वाले फरमान पर उमर अब्दुल्ला का आया ये बयान

श्रीनगर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार के विवादास्पद कांवर यात्रा आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को जानना चाहा कि क्या अमरनाथ और वैष्णो देवी तीर्थयात्रा भी मुसलमानों के बिना संभव होगी। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि अगर (कांवड़ यात्रा) आदेश का मकसद मुसलमानों को दूर रखना है, तो भगवान के लिए, मुझे बताएं, जब (अमरनाथ) यात्रा यहां (जम्मू-कश्मीर) होती है...तो यह मुसलमानों के बिना संभव नहीं है। अपनी बात को विस्तार से बताते हुए उन्होंने माता वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का उदाहरण भी दिया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने कहा कि अमरनाथ यात्री मुसलमानों के कंधों पर यात्रा करते हैं। जो लोग माता वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों को घोड़ों या पिठुओं (कुली) पर ले जाते हैं...वे किस धर्म के हैं? वहां, भाजपा धर्म नहीं देखती है। अब्दुल्ला की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई तक भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के व्यापक आलोचना वाले आदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जारी किए गए इसी तरह के निर्देशों पर रोक लगाने के एक दिन बाद आई है। पार्टी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों पर शासन करती है। इसके निर्देश की भाजपा सहयोगियों ने भी आलोचना की, उत्तर प्रदेश ने वार्षिक कंवर तीर्थयात्रा के मार्गों पर भोजनालयों और खाद्य स्टालों को उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया; विपक्ष ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी मुस्लिम समुदाय का 'आर्थिक बहिष्कार' करने की कोशिश कर रही है।

सावन के पहले सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने लाखों कांवड़ियों को हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा पारित निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। योगी का ये फैसला इसलिए आया था क्योंकि कई दुकान, ढाबे और होटल मिले जिनके नाम तो हिंदू थे लेकिन मालिक मुसलमान। ऐसे में सीएम योगी ने आदेश दिया कि सही नाम के साथ ही दुकान चलानी होगी। इस सख्ती के बाद कई दुकानों ने अपने असली नाम लगाए। योगी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो गए, बुद्धिजीवि बौखला गए। योगी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें कांवरिया मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि दुकानदारों सिर्फ खाने का प्रकार बताने की जरूरत है।

कफ सिरप को लेकर शक निकला सही....क्वालिटी टेस्ट में फेल

नई दिल्ली। कफ सिरप को लेकर भारत की फार्मा कंपनियों पर दुनिया के कई देशों में सवाल उठने के बाद सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 100 कफ सिरप क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गांबिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार खांसी की सिरप में जो टॉक्सिन मौजूद थी वहीं टॉक्सिन इन सिरप में भी पाया गया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक डाइएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्राइकोल पाए जाने की वजह से 100 कंपनियों के कफ सिरप को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की श्रेणी में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि डीईजी/ईजी, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ, पीएच वॉल्यूम के आधार पर कफ सिरप को एनएसक्यू की श्रेणी में रखा गया है। 7087 बैच दवाओं की जांच की गई जिसमें से 353 को एनएसक्यू की श्रेणी में रखा गया। वहीं 9 सैंपल में डीईजी और ईजी की मात्रा थी। गुणवत्ता ठीक ना होने की वजह में डीईजी और ईजी की उपस्थिति के अलावा असुरक्षित सप्लाई चेन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल बल्क टेस्टिंग में फेल होने को बताया गया है। कई देशों में बच्चों की मौत के बाद भारत में बनने वाली कफ सिरप पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके बाद सरकारी और प्राइवेट लैब्स में इनकी जांच की जा रही है। डीजीसीई ने राज्यों के ड्रग कंट्रोलर्स से कहा है कि एक्सपोर्ट के लिए बनाई जा रही कफ सीरप की गंभीरता से जांच की जाए। इसके आलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेड ट्रेड ने भी कफ सिरप के निर्यातकों को निर्देश दिया कि दवा विदेश भेजने से पहले सरकारी लैब में टेस्ट कराए।

'दिशाहीन, जनविरोधी, कोई विजन नहीं, सिर्फ राजनीतिक मिशन है', मोदी सरकार के बजट पर भड़कीं ममता बनर्जी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 को 'राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और गरीब विरोधी' करार दिया और राज्य को 'वंचित' करने के लिए केंद्र की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पश्चिम बंगाल ने क्या गलती की है कि उसे केंद्र द्वारा 'वंचित' किया गया है। बजट को लेकर ममता ने एक बयान में कहा कि यह दिशाहीन, जनविरोधी, कोई विजन नहीं, सिर्फ राजनीतिक मिशन है। मुझे कोई रोशनी नहीं दिखती, अंधेरा है।

ममता ने कहा कि वे चुनाव के दौरान बड़े-बड़े दावे और वादे करते हैं। लेकिन वोट मिलने के बाद वे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों के लोगों को यह याद रखना चाहिए। सिक्किम को चीजें मिलने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दार्जिलिंग को वंचित रखना ठीक नहीं है। यह बजट जनविरोधी है, गरीब विरोधी है और आम लोगों के लिए नहीं है।' यह एक पार्टी को खुश करने वाला बजट है। यह राजनीतिक पूर्वाग्रहों से भरा बजट है।

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि मैं इसे छेड़छाड़ वाला बजट कहता हूं...प्रमुख समस्याएं - 9.2प्र. पर बेरोजगारी और 5प्र. पर मुद्रास्फीति - का बिल्कुल भी समाधान नहीं किया गया है। राज्यों को उनका उचित हिस्सा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को फायदा हुआ। यह बिल्कुल भी अच्छा बजट नहीं है। उन्होंने बुनियादी ढांचे में सब कुछ निवेश किया है, जिसे आकार लेने में काफी समय लगेगा। इसलिए, यह कोई बुद्धिमानी भरा बजट नहीं है।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि पिछले दस सालों में बजट से आम आदमी, किसानों, छात्रों को क्या मिला?...पहले सिर्फ एक राज्य गुजरात के लिए बजट बनता था, अब इसमें दो राज्य और जुड़ गए हैं...पहली बार ,मैंने देखा है कि देश के कल्याण के लिए नहीं बल्कि सरकार बचाने के लिए बजट बनाया गया है।' विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भाजपा के सहयोगियों और 'क्रोनीज़' को खुश करना है। कांग्रेस नेता ने दस्तावेज़ को 'कुर्सी बचाओ' बजट बताया और आरोप लगाया कि यह कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र से नकल किया गया था।

राहुल ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि 'कुर्सी बचाओ' बजट। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''सहयोगियों को खुश करने के लिए अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। अपने मित्रों को खुश किया गया, 'एए' को लाभ दिया गया, लेकिन आम भारतीय को कोई राहत नहीं दी गई।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले कुछ बजट का 'कॉपी-पेस्ट' किया गया है।''

लोकसभा स्पीकर की बेटी अंजलि पहुंची हाईकोर्ट

-झूठे आरोपों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया दायर

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईआरपीएस अधिकारी अंजलि बिरला ने झूठे आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अंजलि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी हैं। वह सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने की मांग कर रही हैं जिनमें उन पर झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने (अंजलि) अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अपने मानहानि मुकदमे में, अंजलि बिरला ने कहा है कि कई सोशल मीडिया पोस्ट उनके बारे में भ्रामक और झूठी जानकारी फैला रहे हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि ये प्रकृति में मानहानिकारक हैं।

अंजलि ने अपनी याचिका में कहा है कि फैलाए जा रहे झूठे और निराधार आरोप वादी की प्रतिष्ठा को गैरकानूनी रूप से नुकसान पहुंचाने और मानहानिकारक आख्यानों के जरिए से खड़े होने के स्पष्ट इरादों का संकेत देते हैं। अकेले इस दावे के आधार पर, वादी का मानना है कि वर्तमान मुकदमा अपनी योग्यता के आधार पर सफल होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस नवीन चावला की बेंच इस मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गई। अंजलि की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने मामले को सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।

सूत्रों के मुताबिक मुकदमे में कहा गया है कि कई व्यक्ति बिना किसी सच्चाई या सबूत के वादी की पेशेवर प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के खिलाफ विवाद पैदा करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से वादी को ही निशाना बना रहे हैं। यह मुकदमा प्रतिवादियों को वादी और उसके परिवार के सदस्यों, जिसमें उनके पिता ओम बिरला, जो लोकसभा के स्पीकर हैं की भी प्रतिष्ठा को धूमिल करने से रोकने के लिए लाया जा रहा है।

महाराष्ट्र में अजित गुट के लगाए पोस्टर से मुख्यमंत्री गायब, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं?

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम से तनाव के संकेत मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ा गया। इसके बाद अब विधानसभा सीटों के लिए रस्साकशी शुरु हो गई है। अब अजित पवार की एनसीपी की ओर से लड़की-बहिन योजना के पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पिछले महीने विधानसभा में अपने बजट भाषण में 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन' योजना की घोषणा की थी। अजित एकनाथ शिंदे सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। ये पोस्टर सोमवार को अजित पवार के जन्मदिन के अवसर पर अहमदनगर जिले के पारनेर, अहमदनगर, श्रीगोंडा और कर्जत-जामखेड विधानसभा क्षेत्रों के उनके दौरे के पहले लगाए गए थे।

यहां आयोजित कार्यक्रमों में अजित पवार ने महिलाओं को संबोधित कर योजना का उल्लेख 'माझी लाडकी बहिन' के रूप में किया, जबकि 'मुख्यमंत्री' शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया। इस योजना के तहत उन परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम है। डिप्टी सीएम पवार ने बीते महीने बजट के दौरान इस योजना का ऐलान किया था। अजित इस बीच अहमदनगर, श्रीगोंजा, करजात-जमखेद क्षेत्रों में गए ताकि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बढ़त बनाई जा सके। उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और इसी दौरान ये पोस्टर सामने आए। उनके इन दौरों के समय ही पिंक कलर में पोस्टर लगाए गए थे। इनमें अजित पवार की तस्वीरें तो थीं, लेकिन सीएम का जिक्र तक नहीं था।

बजट कागजों पर अच्छा, किसानों को कोई फायदा नहीं: टिकैत

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए और नौ प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की जिसमें उत्पादकता बढ़ाना शामिल है। अपने बजट प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने कहा कि अगले दो साल में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी।

मोदी सरकार बजट किसान नेता राकेश टिकैत को पसंद नहीं आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र को कागजों पर यह बजट अच्छा लग सकता है लेकिन जमीन पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे उन कंपनियों को फायदा होगा जो किसानों को जैविक खेती सिखाएंगी। उन्होंने मांग की कि सरकार को फसलों की कीमत चुकानी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करना चाहिए था।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। अगले दो सालों में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। पांच राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना एक नीतिगत लक्ष्य होगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहकारी क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के कार्यान्वयन की सुविधा भी देगी। उन्होंने झींगा ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद देने की घोषणा की।

भारत में 2050 तक 34 करोड़ 60 लाख हो जाएगी बुजुर्गों की संख्या

-महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन में अधिक निवेश की जरुरत

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूएनएफपीए-इंडिया की रेजिडेंट प्रतिनिधि एंड्रिया वोजनार ने विश्व जनसंख्या दिवस के कुछ दिनों बाद जनसंख्या के उन प्रमुख रुझानों को रेखांकित किया, जिन्हें भारत सतत विकास में तेजी लाने के लिए प्राथमिकता दे रहा है।

इनमें युवा आबादी, वृद्ध जनसंख्या, शहरीकरण, प्रवासन और जलवायु के अनुसार बदलाव करना शामिल हैं। ये कारक सभी देश के लिए अनूठी चुनौतियां और अवसर पेश करते हैं। वोजनार ने कहा कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 2050 तक दोगुनी होकर 34 करोड़ 60 लाख हो जाने का अनुमान है। देश में खासकर उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन में अधिक निवेश किए जाने की जरूरत है, जिनके अकेले रह जाने और गरीबी का सामना करने की अधिक आशंका है। इसलिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन योजनाओं में निवेश बढ़ाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि खासकर वृद्ध महिलाओं के लिए ऐसा करना आवश्यक है, जिनके अकेले रहने और गरीबी का सामना करने की अधिक आशंका है।

यूएनएफपीए-इंडिया प्रमुख ने कहा कि भारत में युवा आबादी काफी है और 10 से 19 वर्ष की आयु के 25 करोड़ 20 लाख लोग हैं। उन्होंने जिक्र किया कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सृजन में निवेश करने से इस जनसांख्यिकीय क्षमता को भुनाया जा सकता है और देश को सतत प्रगति की ओर अग्रसर किया जा सकता है। वोजनार ने कहा कि भारत में 2050 तक 50 प्रतिशत शहरी आबादी होने का अनुमान है, इसलिए झुग्गी बस्तियों की वृद्धि, वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट शहरों, मजबूत बुनियादी ढांचे और किफायती आवास का निर्माण महत्वपूर्ण है।

उन्होंने आगे कहा कि शहरी योजनाओं में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जरूरतों, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा एवं नौकरियों तक पहुंच को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके। वोजनार ने यह भी कहा कि आंतरिक और बाहरी प्रवासन को प्रबंधित करने के लिए अच्छे से सोच-विचार कर योजना बनाने, कौशल विकास करने और आर्थिक अवसर वितरण की आवश्यकता होती है।

छात्र यहां बसने की उम्मीद लेकर ना आएं : कनाडा

ओटावा । कनाडा के इमिग्रेशन मिनस्टर ने भी एक बयान में कहा है कि स्टडी वीजा पर आने वाले छात्र यहां बसने की उम्मीद लेकर ना आएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय और विक्टोरिया विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों का कहना है कि उनके अंतरराष्ट्रीय छात्र नामांकन स्तर पहले से ही 30 प्रतिशत की सीमा से नीचे हैं। ऐसे में नई गाइडलाइन से उन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांक क्वांटलेन पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय ने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए अपने 36 प्रतिशत नामांकन के साथ नई सीमा को पार कर लिया है। इस महीने प्रभावी होने वाले दिशानिर्देशों में आगामी वर्ष से तय समय सीमा को फॉलो करना होगा। कनाडा सरकार वर्तमान में तेजी से जनसंख्या वृद्धि के बीच आप्रवासन को धीमा करने के प्रयास में विदेशी छात्रों के लिए दीर्घकालिक वीजा जारी करने की भी समीक्षा कर रही है। इमिग्रेशन मिनस्टर मार्क मिलर ने विदेशी छात्रों की संख्या को घरेलू बाजार की मांग के अनुपात में रखने पर जोर दिया है। कनाडा की नीति शिक्षित आप्रवासियों और छात्रों का स्वागत करने की रही है लेकिन हालिया समय में उसकी नीति में बदलाव आया है। मंत्री मिलर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि स्टडी वीजा को कनाडा में बसने की गारंटी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। स्टडी वीजा पढ़ाई की इजाजत देता है और उसे उसी तरह से देखा जाना चाहिए। बता दें कि कनाडा में विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया (बीसी) प्रान्त की सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीसी सरकार ने सार्वजनिक पोस्ट सेकेंडरी संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय छात्र नामांकन को कुल छात्रों के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन एंड स्किल मिनिस्ट्री ने कहा है कि छात्रों के नामांकन की सीमा तय करने का मकसद संस्थानों पर दबाव कम करना है। गाइडलाइन में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रणनीतिक योजना प्रस्तुत करनी होगी। कॉलेजों की निगरानी प्रांत के प्रशासन की ओर से की जाएगी।

15 राज्यों के गवर्नर हेरिस के समर्थन में, लोकप्रियता में ट्रंप पिछड़े

न्यूयॉर्क । वर्तमान राष्ट्रपति वाइडेन के चुनाव मैदान से हटने और कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आने के बाद, अमेरिका की राजनीति में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कमला हैरिस का नाम सामने आते ही रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में 10 फ़ीसदी की गिरावट देखी जा रही है। जिन राज्यों से ट्रंप को भारी समर्थन मिल रहा था। उन राज्यों में भी कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद ऑनलाइन सर्वे में ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट आई है। कमला हैरिस को 24 घंटे के अंदर 15 डेमोक्रेटिक गवर्नर तथा 55 सीनेटरों का समर्थन मिला है। राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का नाम सामने आते ही, अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रणनीति को बदलना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस के पक्ष में जो सहानुभूति की लहर चल रही है। उसका मुकाबला करना पड़ेगा। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति पद के लिए पहली अश्वेत महिला हैं। अमेरिका की 25 फ़ीसदी आबादी अश्वेत मतदाताओं की है। कमला हैरिस गर्भपात के अधिकार की समर्थक रही हैं। कमला हेरिस अटॉर्नी रह चुकी हैं। वह ट्रंप के क्रिमिनल रिकॉर्ड को चुनावी प्रचार का हथकंडा बनाएंगी। ट्रंप के लिए कमला हेरिस को घेरना अब मुश्किल हो जाएगा।

10 घंटे में 435 करोड़ का चंदा – कमला हैरिस की उम्मीदवारी घोषित होते ही 10 घंटे के अंदर 435 करोड रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ। 2020 के चुनाव में एक दिन के अंदर 295 करोड रुपए का रिकॉर्ड चंदा एकत्रित हुआ था। इस बार 10 घंटे में ही 435 करोड रुपए इकट्ठे हो गए।

अमेरिका के फ्लोरिडा का फोर्ड लाडरडेल अरबपतियों का नया पसंदीदा शहर

न्यूयॉर्क । अमेरिका के फ्लोरिडा का फोर्ट लाडरडेल शहर अरबपतियों का नया ठिकाना बन रहा है। फ्लोरिडा के इस शहर में बड़ी संख्या में अरबपति आकर बस रहे हैं। यहां की प्रॉपर्टी में याटपार्क करने की सुविधा है। जैफ बेजोस,कैन ग्रिफिन,लियोनेल मेसी जैसे दिग्गज यहां पर प्रॉपर्टी ले चुके हैं। अन्य अरबपति और ख़रबपति भी यहां प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में यहां संपत्तियों की कीमतें बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। डेढ़ साल पहले जो बंग्ला ढाई सौ करोड रुपए का था। अब वह 400 करोड रुपए में बिका है। कहा जा रहा है, अरबपतियों का यह नया गढ़ बन गया है। जिसके कारण आने वाले समय में यहां प्रॉपर्टी की कीमत और भी तेजी के साथ बढ़ेगी।

सऊदी सरकार का फैसला, अब स्थानीय लोगों को दी जाएगी नौकरी, भारतीयों पर मंडराने लगा खतरा

रियाद। सऊदी अरब की सरकार ने नौकरियों में स्थानीय लोगों को ज्यादा मौका देने का फैसला लिया है। सऊदी अरब ने निजी क्षेत्र में 25 फीसदी इंजीनियरिंग नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी हैं। नौकरियों को लोकेलाइज करने का यह फैसला 21 जुलाई से लागू कर दिया गया है। देश के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय, नगर निगम और आवास मंत्रालय ने इस संबंध में ये फैसला किया है। स्थानीयकरण का ये फैसला इंजीनियरिंग व्यवसायों में पांच या उससे ज्यादा कामगारों को रोजगार देने वाले निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। छोटे प्रतिष्ठानों, जिनमें कर्मचारियों की संख्या चार तक है, वहां ये नियम लागू नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ये फैसला कई क्षेत्रों में देश के पुरुष और महिला नागरिकों के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करेगा। सऊदी के इस फैसले से स्थानीय लोगों को नौकरी मिलने में आसानी होगी। देश में केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, फ्लाइट इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जॉब काफी संख्या में हैं। सऊदी सरकार ने इंजीनियरिंग में रोजगार बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। प्रतिष्ठानों को मदद के लिए मानव संसाधन विकास कोष एचएडीएएफ ने प्रोत्साहन और सहायता, भर्ती प्रक्रियाओं और उपयुक्त श्रमिकों की खोज, प्रशिक्षण और व्यावसायिक योग्यता, भर्ती प्रक्रिया और कैरियर निरंतरता का समर्थन का फैसला लिया है। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने 2030 तक बेरोजगारी को सात फीसदी तक कम करने के लिए कई क्षेत्रों में श्रमिकों के सऊदीकरण की घोषणा की है, जो आय स्रोतों में विविधता लाने और तेल पर निर्भरता को कम करने के विजन 2030 के लक्ष्य के अनुरूप है। सऊदी सरकार के इस फैसले का सीधा असर भारतीय कामगारों पर भी होगा। सऊदी में काम करने वालों की संख्या करीब 26 लाख है। सऊदी में भारतीय करीब हर क्षेत्र में नौकरियां कर रहे हैं। इसमें ड्राइवर, सफाईकर्मी, रसोइया, नर्स के अलावा इंजीनियरिंग क्षेत्र की नौकरियां शामिल हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 के तहत सऊदी अरब के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। इसी क्रम में सऊदी में नौकरियों में आरक्षण का फैसला लिया गया है।

ट्रम्प पर हमले में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने माना हुई बड़ी चूक

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर हुए हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है जिसमें बताया गया है कि सीक्रेट सर्विस से भारी चूक हुई है। सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर किम्बरली ने माना कि ट्रम्प पर हमला दशकों में

सबसे बड़ी चूक है। संसद में अपनी पेशी के दौरान किम्बरली चिटेल ने यह बयान दिया। डोनाल्ड ट्रम्प पर हमले को रोकने दशकों में सीक्रेट सर्विस की बड़ी नाकामी है। इसकी वजह से ट्रंप घायल हो गए थे। हालांकि पहली गोली चलाने के 26 सेकंड बाद एक सीक्रेट सर्विस स्नाइपर ने हमलावर को मार गिराया था। हमले के बाद डायरेक्टर किम्बली चीटल के खिलाफ सुनवाई चल रही है। रिपब्लिकन कमिटी के अध्यक्ष जेम्स कॉमर ने कहा कि इस घटना को रोका जा सकता था। राष्ट्रपति जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के बाद राष्ट्रपति पद के स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर की सुरक्षा करने का आदेश यू.एस. सीक्रेट सर्विस' को दिया था। कैनेडी के अभियान कार्यक्रमों ने समर्थकों और उनके संदेश में रुचि रखने वाले लोगों की बड़ी भीड़ को आकर्षित किया है। बता दें पेंसिल्वेनिया में गत शनिवार को एक रैली में हुई गोलीबारी में ट्रंप बाल-बाल बच गए और उन्हें गंभीर चोट नहीं आई थी। हमले की स्वतंत्र समीक्षा की गई।

ताइवान में एक महिला सैनिकों को नदी के करीब किसी दुश्मन को रोकने के लिए बारुदी सुरंग लगाते हुए देखती हुई।

नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर 'स्पष्ट और दृढ़', भारतीय क्षेत्रों पर दावा

-पीएम बनते ही ओली ने उठाया सीमा विवाद का मुद्दा

काठमांडू। नेपाल के नवनियुक्त पीएम के.पी.ओली शर्मा ने कहा कि भारत के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों को कूटनीतिक तंत्र के जरिए हल करने के लिए तैयार है और काठमांडू अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में 'स्पष्ट और दृढ़' है। प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने के एक दिन बाद सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए ओली ने कहा कि सरकार इस बात पर दृढ़ और स्पष्ट है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख समेत महाकाली नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र नेपाल के हैं। ओली ने कहा कि संघीय संसद और नेपाल सरकार का रुख देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर स्पष्ट और दृढ़ है। उन्होंने कहा कि नेपाल ने एक नया मानचित्र अपनाया है, जिसे 2017 में संविधान में दूसरे संशोधन के जरिए से शामिल किया गया है और इसके अनुलग्नक तीन में उल्लेख किया गया है और हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में अभूतपूर्व राष्ट्रीय सहमति बनी है। ओली ने 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उच्चस्तरीय यात्राओं के दौरान हुई मुलाकातों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तंत्र के जरिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी है। ओली ने कहा कि 4 जनवरी को आयोजित नेपाल-भारत विदेश मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग की सातवीं बैठक के दौरान नेपाल-भारत सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी और नेपाल-भारत सीमा के शेष हिस्सों पर लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

चीनी भाई-भाई, इजरायल-यूएस की नाक के नीचे बीजिंग ने 17 साल पुराने 2 दुश्मनों की दोस्ती कराई

बीजिंग (एजेंसी)। इजरायल और फिलिस्तीन की जंग रूकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बढ़ती ही जा रही है। इन सब के बीच चीन से ऐसी खबर सामने आई है जो अमेरिका और इजरायल दोनों की टेंशन बढ़ा सकती है। हूती की लड़ाई अलग लेवल पर पहुंच गई है तो हिज्जबुल्ला ने भी अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। इजरायल के ऊपर इसका असर दिखने लगा है। कुछ वक्त पहले की बात है जब रूस में हमास और फिलिस्तीन के अन्य संगठनों की मीटिंग हुई थी। इसके पीछे का मकसद था कि जंग के खत्म होने के बाद गाजा-वेस्ट बैंक के इलाके में सारे फिलिस्तीनी मिलकर काम करे। अब हाल में ही चीन में एक मीटिंग हुई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन की इस मीटिंग में फतह, हमास और इसके अलावा 14 अलग अलग आजाद फिलिस्तीन के एक्टिव संगठन मौजूद थे। इन सारे विभिन्न संगठनों में आपस में ही गतिरोध रहा है और जिसका फायदा इजरायल को मिलता रहा है। चीन के विदेश मंत्री और हमास के अधिकारियों ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी फिलिस्तीनी गुटों हमास और फतह ने चीन की मध्यस्थता में हुई एक बैठक में इजराइल के साथ युद्ध के बाद कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा के लिए एक अंतरिम राष्ट्रीय सुलह सरकार बनाने पर सहमति व्यक्त करते हुए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

बीजिंग में तीन दिनों की वार्ता के बाद 12 अन्य फिलिस्तीनी गुटों के साथ समूहों के प्रतिनिधियों ने एकता के लिए काम करने का वादा किया। यह हमास और फतह के बीच लंबे समय से खंडित संबंधों के बीच हुए कई सुलह समझौतों में से नवीनतम है, जिनमें से किसी के भी कारण अभी तक विवाद का अंत नहीं हुआ है। इज़राइल ने वहां शत्रुता समाप्त होने के बाद

गाजा पर शासन करने में हमास या फतह की भूमिका से भी इंकार कर दिया है। गहरा विभाजन 2007 में शुरू हुआ जब फतह को क्षेत्र से हिंसक तरीके से बेदखल करने के बाद हमास गाजा में एकमात्र शासक बन गया। यह फिलिस्तीनी राष्ट्रपति और फतह नेता महमूद अब्बास द्वारा हमास के नेतृत्व वाली एकता सरकार को भंग करने के बाद आया, जब हमास ने एक साल पहले राष्ट्रीय चुनाव जीता था। तब से, फतह-प्रभुत्व वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण को वेस्ट बैंक के केवल कुछ हिस्सों का प्रभारी छोड़ दिया गया है।

इजराइल-हमास युद्ध से क्या चाहता है चीन?

बीजिंग ने पहले अप्रैल में हमास और फतह के बीच वार्ता की मेजबानी की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा चीन और फिलिस्तीन भरोसेमंद भाई और अच्छे साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि चीन एकता और सुलह की दिशा में सभी संबंधित पक्षों के साथ अथक प्रयास करेगा। विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि सुलह फिलिस्तीनी गुटों के लिए एक आंतरिक मामला है, लेकिन साथ ही, इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है।

कनाडा में फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया... भारत विरोधी टिप्पणियां लिखी गई

कनाडा (एजेंसी)। कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। खालिस्तान समर्थकों पर कनाडा में एक्शन ना होकर उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में कनाडा के एडमोंटन में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी टिप्पणियां लिख दी गई। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने बताया कि बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। साथ ही कहा कि ग्रैफिटी के द्वारा भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य पर भी हमला किया गया।

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने पोस्ट में लिखा, कनाडा के एडमोंटन में मंदिर आज सुबह एक और हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। मंदिर पर कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ हिंदू सदस्यों में से एक के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। हम इस घटना की निंदा करते हैं जो पिछले कई हमलों का ही हिस्सा है जिनमें से ज्यादातर के लिए खालिस्तान समर्थक दोषी हैं।

सांसद आर्य ने कहा है कि कनाडा में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आर्य ने कहा, एडमॉन्टन में स्वामीनारायण मंदिर में फिर से तोड़फोड़ की गई है। पिछले कुछ सालों में ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के दूसरे जगहों पर हिंदू मंदिरों को ग्राफिटी के जरिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

सांसद चंद्र आर्य ने कहा, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं, खालिस्तानी चरमपंथी हिंसा फैलाने के बावजूद आसानी से बच जाते हैं। फिर से मैं इस रिकॉर्ड पर रखूंगा। हिंदू कनाडाई इससे चिंतित हैं। मैं फिर से कनाडा की कानूनी एजेंसियों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की गुजारिश करता हूं, इससे पहले कि ये बयानबाजी लोगों के खिलाफ शारीरिक हिंसा में तब्दील हो जाए।

पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कबाइलियों ने बुलाया जिरगा, ऑपरेशन का किया विरोध

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तानी सेना का देश में विरोध शुरू हो गया है। पश्तून कबाइलियों ने सेना के चरमपंथ विरोधी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। खैबर-पख्तूनख्वा (केपी) के सीएम हाउस पर कबाइलियों का जिरगा (बैठक) बुलाया गया, जिसमें कई बड़े कबाइली नेता शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिरगा में नेताओं ने ऑपरेशन अज्म-ए-इस्तेहकाम का विरोध किया। इसके साथ ही पाकिस्तान को गुड तालिबान और बैड तालिबान दोनों को खत्म करने को कहा गया है। गुड तालिबान पाकिस्तान में उन तालिबानी आतंकवादियों को कहा जाता है, जिनके पाकिस्तानी सेना से अच्छे संबंध हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक जिरगा की अध्यक्षता खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर ने की। इसमें केपी के मुख्य सचिव, आईजी पुलिस, बन्नू के कमिश्नर और क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर ने भाग लिया। जिरगा में कबाइली नेताओं ने सीएम गंडापुर के सामने 11 मांगे रखी। उन्होंने मांग की कि तलाशी अभियान के दौरान मदरसों, घरों और व्यक्तियों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए।

जिरगा नेताओं ने कहा कि मदरसों और घरों पर रेड करना गलत होगा और इससे लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय प्रशासन को क्षेत्र में तालिबान से निपटने के लिए पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही आतंकवाद निरोधक विभाग को पूरी तरह सक्रिय करने और आतंकवादियों और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने का आग्रह किया है।

पश्तूनों के विरोध का असर पाकिस्तान में दिखाई देने लगा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन अज्म-ए-इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि आतंकवाद विरोधी अभियान है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक मजबूत लॉबी नेशनल एक्शन प्लान को सफल नहीं होने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि अज्म-ए-इस्तेहकाम की तुलना जर्ब-ए-अज्ब और राह-ए-निजात जैसे पिछले अभियानों से करना ठीक नहीं है।

सऊदी सरकार का फैसला, अब स्थानीय लोगों को दी जाएगी नौकरी, भारतीयों पर मंडराने लगा खतरा

रियाद (एजेंसी)। सऊदी अरब की सरकार ने नौकरियों में स्थानीय लोगों को ज्यादा मौका देने का फैसला लिया है। सऊदी अरब ने निजी क्षेत्र में 25 फीसदी इंजीनियरिंग नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी हैं। नौकरियों को लोकेलाइज करने का यह फैसला 21 जुलाई से लागू कर दिया गया है।

देश के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय, नगर निगम और आवास मंत्रालय ने इस संबंध में ये फैसला किया है। स्थानीयकरण का ये फैसला इंजीनियरिंग व्यवसायों में पांच या उससे ज्यादा कामगारों को रोजगार देने वाले निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। छोटे प्रतिष्ठानों, जिनमें कर्मचारियों की संख्या चार तक है, वहां ये नियम लागू नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ये फैसला कई क्षेत्रों में देश के पुरुष और महिला नागरिकों के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करेगा। सऊदी के इस फैसले से स्थानीय लोगों को नौकरी मिलने में आसानी होगी। देश में केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, फ्लाइट इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जॉब काफी संख्या में हैं।

सऊदी सरकार ने इंजीनियरिंग में रोजगार बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। प्रतिष्ठानों को मदद के लिए मानव संसाधन विकास कोष एचएडीएएफ ने प्रोत्साहन और सहायता, भर्ती प्रक्रियाओं और उपयुक्त

श्रमिकों की खोज, प्रशिक्षण और व्यावसायिक योग्यता, भर्ती प्रक्रिया और कैरियर निरंतरता का समर्थन का फैसला लिया है। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने 2030 तक बेरोजगारी को सात फीसदी तक कम करने के लिए कई क्षेत्रों में श्रमिकों के सऊदीकरण की घोषणा की है, जो आय स्रोतों में विविधता लाने और तेल पर निर्भरता को कम करने के विजन 2030 के लक्ष्य के अनुरूप है।

सऊदी सरकार के इस फैसले का सीधा असर भारतीय कामगारों पर भी होगा। सऊदी में काम करने वालों की संख्या करीब 26 लाख है। सऊदी में भारतीय करीब हर क्षेत्र में नौकरियां कर रहे हैं। इसमें ड्राइवर, सफाईकर्मी, रसोइया, नर्स के अलावा इंजीनियरिंग क्षेत्र की नौकरियां शामिल हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 के तहत सऊदी अरब के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। इसी क्रम में सऊदी में नौकरियों में आरक्षण का फैसला लिया गया है।

हमारा दृष्टिकोण भविष्य पर केंद्रित है, डोनाल्ड ट्रंप का अतीत पर: हैरिस

-मध्यम वर्ग का निर्माण मेरे राष्ट्रपति पद का एक निर्णायक लक्ष्य

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। हैरिस ने विलमिंगटन, डेलावेयर में जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर व्यक्तिगत हमला करते हुए ट्रम्प को धोखेबाज, जालसाज और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाला इंसान बताया है। हैरिस ने कहा कि उनका दृष्टिकोण भविष्य पर केंद्रित है जबकि ट्रंप का अतीत पर। इस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन फोन द्वारा इसमें शामिल हुए।

हैरिस ने बाइडेन के स्टाफ को ही अपने अभियान में लगा लिया है। बाइडेन ने भी अपने स्टाफ से कमला हैरिस के लिए दिल से काम करने को कहा है। हैरिस के अभियान ने केवल 24 घंटे में 81 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। डेमोक्रेट उत्साहित दिख रहे हैं और पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन के खराब प्रदर्शन के बाद अब हैरिस के पीछे खड़े हैं। 20,000 से ज्यादा नए वालंटियर अभियान में जुड़ गए हैं। हैरिस ने अपने भाषण में एक जिला अदालत से लेकर कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल बनने तक के अपने करियर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने उन लोगों का सामना किया जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे धोखेबाज जो कंज्यूमर्स को लूटते हैं, जो अपने लाभ के लिए नियम तोड़ते हैं। उन्होंने कहा मेरी बात सुनिए क्योंकि मैं डोनाल्ड ट्रंप टाइप लोगों को जानती हूं।

हैरिस ने कहा डोनाल्ड ट्रंप एक कॉलेज ट्रम्प यूनिवर्सिटी चलाते थे, जिसे छात्रों को ठगने के लिए 25 मिलियन डॉलर का भुगतान करना पड़ा। 2007-2008 के वित्तीय संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों से मुकाबला किया और कैलिफोर्निया के परिवारों के लिए 20 बिलियन डॉलर जीते। उन बैंकों को धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप को हाल ही में धोखाधड़ी के 34 मामलों में दोषी पाया गया है। हैरिस ने ट्रंप के साथ मुकाबले को अमेरिका के लिए दो विपरीत धाराओं की लड़ाई के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप देश को पीछे ले जाना चाहते हैं जब हमारे साथी अमेरिकियों को पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार नहीं थे। हम एक ऐसे

उज्जवल भविष्य में विश्वास करते हैं जो सभी अमेरिकियों के लिए जगह बनाए। हम एक ऐसे भविष्य में विश्वास करते हैं जहां हर व्यक्ति को न केवल गुज़र-बसर करने का बल्कि आगे बढ़ने का मौका मिले। इन सबका मतलब यह है कि मध्यम वर्ग का निर्माण मेरे राष्ट्रपति पद का एक निर्णायक लक्ष्य होगा।